



मेलबर्न में पीएम मोदी की इस बात पर गूंज उठी तालियां

दूध में घुलने वाली चीनी की तरह हैं भारतीय

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बदलती वैश्विक पहचान और विकास की रफ्तार का दमदार संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जहां भी जाते हैं, वहां सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और संस्कृति की ऐसी मिठास घोल देते हैं, जो पूरी दुनिया को जोड़ती है। भारतीयों की तुलना दूध में घुलने वाली चीनी से करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घर का दूध और सब्जियां भले ऑस्ट्रेलिया की हों, लेकिन उनसे बनने वाली चाय और खाने का असली स्वाद भारतीय संस्कृति और मसालों से आता है।

पीएम मोदी ने कहा, हम भारतीय दूध में घुलने वाली चीनी की तरह हैं, जो उसे और भी मीठा बना देती है। हम भारतीय दुनिया में अपने प्यार की मिठास घोलते रहते हैं। घर

भारत-आस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वार्ता में हुए कई बड़े समझौते



मेलबर्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देते हुए सविल न्यूविलयर एनर्जी, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज , साइबर सुरक्षा और सलाई वेन जैसे अहम क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ व्यापक द्विपक्षीय

वार्ता की। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के एक दिन बाद हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की बैठक के बाद दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा पर संयुक्त घोषणा जारी की। इसके अलावा ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त बयान तथा साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और सलाई वेन में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा रोडमैप भी जारी किया गया।

सपनों और ऊंची आकांक्षाओं की सबसे मजबूत नींव देश के लोग हैं। ‘वी द पीपल’ और ‘नागरिक देवो भव’ का मंत्र आज देश के सुशासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन चुका है।

आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के ठिकानों पर विस्फोट हो रहे थे और उनकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 की अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा को याद करते हुए कहा कि वह 28 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी। उस समय उन्होंने भारतीय समुदाय से कहा था कि अगली यात्रा के लिए उन्हें फिर 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पिछले 12 वर्षों में यह मेरी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा है। एक तरह से यह हैट्रिक है।

बेलगावी में आज से तीन दिवसीय मंथन



■ संगठन के विस्तार, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और देश के मौजूदा हालात समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी

नईदिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होगी। संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान होने वाली यह बैठक संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें देशभर के 46 प्रांतों और 11 क्षेत्रों के प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक भाग लेंगे। इसके अलावा संघ से जुड़े 32 विभिन्न संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तीन दिनों तक चलने वाले इस मंथन में संगठन के विस्तार, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और देश के मौजूदा हालात समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक में पिछले एक वर्ष के दौरान संगठन के कामकाज की विस्तृत

समीक्षा की जाएगी। खास तौर पर शताब्दी वर्ष के अवसर पर देशभर में शुरू किए गए शाखा विस्तार अभियान का आकलन होगा। यह देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों में नई शाखाएं शुरू हुईं, किन स्थानों पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली और आने वाले महीनों में अधिक से अधिक नई शाखाएं शुरू करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए।

बैठक में इस वर्ष आयोजित संघ के विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही शताब्दी वर्ष के तहत विजयादशमी 2026 तक प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि समाज के अधिक से अधिक लोगों तक संगठन की पहुंच कैसे बढ़ाई जाए और शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को व्यापक जनभागीदारी के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए।

92% लोगों को जीवन में एक बार होगा कैंसर

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में खुलासा

बीच बड़ी असमानता बनी हुई है।

उच्च आय वाले देशों में स्तन कैंसर से पीड़ित 87 प्रतिशत महिलाएं निदान के पांच वर्ष बाद तक जीवित रहती हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह आंकड़ा केवल 42 प्रतिशत है। तीन में से एक से भी कम देशों ने कैंसर उपचार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) में शामिल किया है।



रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में हर वर्ष करीब 2.06 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आते हैं और लगभग एक करोड़ लोगों की मौत इस बीमारी से होती है। प्रतिदिन 26 हजार से अधिक लोगों की जान जाने के कारण कैंसर, हृदय रोगों के बाद दुनिया में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, 82 प्रतिशत देशों के

पास राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना है, लेकिन इनका लाभ अपेक्षित गति से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।

निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में कैंसर की 20 प्रमुख आवश्यक दवाओं की उपलब्धता केवल नौ से 54 प्रतिशत तक है, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह 68 से 94 प्रतिशत के बीच है। रिपोर्ट में सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र से कैंसर नियंत्रण को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का हिस्सा बनाने, सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया गया है।



रायपुर। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में सरकार गठन के बाद 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने तथा ‘मोर गांवडूभोर पानी’ महाअभियान की उल्लेखनीय उपलब्धियों से संबंधित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 11 लाख आवास पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 11 हितग्राहियों को उनके नए आवास की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान कर सम्मानित किया तथा मोर गांव मोर पानीमहाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित कॉम्पेंडियम का विमोचन किया।

राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून के दौरे पर रहेंगे

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, देशव्यापी छात्रों की गूंज अभियान के तहत शहर के युवाओं से बातचीत करने के लिए 17 जुलाई को देहरादून का दौरा करेंगे। यह दौरा राजस्थान के कोटा में पहले हुए ‘छात्रों की गूंज’ प्रोग्राम के मॉडल पर आधारित होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी के अनुसार, गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में युवाओं से मिलेंगे; उन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारियों के चल रहे होने की पुष्टि की है। राहुल गांधी ने पिछली बार 4 जून को उत्तराखंड का दौरा किया था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अल्मोड़ा में उनकी जनसभा और पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ तय बातचीत को टालना पड़ा था। छात्रों की गूंज अभियान का मकसद छात्रों की समस्याओं को सामने लाना है, जिनमें परीक्षा में गड़बड़ियां और भारत की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बड़ी चुनौतियां शामिल हैं। गांधी ने सबसे पहले कोटा में छात्रों की गूंज महा रैली के ज़रिए इस अभियान की शुरुआत की थी।

बांकीपुर विस सीट से भाजपा प्रत्याशी ने भरा नामांकन पर्चा



पटना। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। पटना समाहरणालय में वह गुरुवार को पहुंचे। इसके बाद अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने बांकीपुर की जनता को नमन किया। उन्होंने बांकीपुर की जनता से साथ देने की अपील की। अभिषेक के साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में जीत तय होने का दावा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक कुमार एक साधारण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में ही यह संभव है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी संगठन और राजनीति में बड़ा दायित्व मिल सके। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की किसी भी पार्टी में इस तरह का अवसर सामान्य कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता।

अखिलेश यादव ने मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की

लखनऊ। आरोपियों से पृच्छाछ जारी रहने के बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे



सनातन धर्म में महापाप बताया और मंदिर ट्रस्ट के पूरी तरह से पुनर्गठन की मांग की। लखनऊ में आध्यात्मिक गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम में उनसे मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि अयोध्या में उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भगवान श्री राम की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हमारे सनातन धर्म में धार्मिक चढ़ावे या दान में चोरी करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। हर गांव और घर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि उन्होंने दान और चढ़ावे का प्रबंधन कैसे किया। हमारा हिंदू धर्म और सनातनी लोग बहुत भावुक हैं; उन्हें इससे गहरा दुख पहुंचा है। सपा प्रमुख ने इस मामले की जांच कर रही सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को खारिज कर दिया।

सपा-कांग्रेस सनातन का अपमान करते हैं : सीएम योगी

बांदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर सनातन परंपराओं का अपमान करने और प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों के विकास का विरोध करने का आरोप लगाया। बांदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल-इंजन सरकार देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम आदित्यनाथ यहां 710 करोड़ रुपये की 229 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों ने हिंदू परंपराओं और सनातन धर्म को अपमानित करना ही अपना एकमात्र ध्येय बना लिया है। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, सपा और कांग्रेस को अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता, उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता, उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का भव्य धाम भी अच्छे नहीं लगते।

वया महाराष्ट्र में आपातकाल लागू कर दिया है : संजय राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की। उन्होंने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री के हालिया टकराव वाले रुख पर सवाल उठाए।



मुख्यमंत्री की चेतावनी का जवाब देते हुए, राउत ने एक्स पर राज्य में शासन के माहौल पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लागू कर दिया गया है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, लूट-पाट और डराना-धमकाना मौजूदा प्रशासन की पहचान बन गए हैं। महाराष्ट्र को एक संस्कारी मुख्यमंत्री की ज़रूरत है! लेकिन क्या किया जा सकता है? खदान तो बस धूल-मिट्टी ही है। क्या देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में इमरजेंसी लगा दी है? सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार, लूट-पाट और भीड़ का राज-यही तो इमरजेंसी है, जिसमें लोगों को बोलने की इजाजत नहीं होती! शिवसेना नेता ने महाराष्ट्र विधानसभा के चल रहे मौनसून सत्र का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए आलोचकों को कड़ी चेतावनी दी।

मुफ्त दवा योजना पर संकट नहीं समाधान की जरूरत

कतिलाल मांडोट

जीवनरक्षक दवाओं की कमी गरीब मरीजों के लिए गंभीर चुनौती लेकिन समय रहते व्यवस्था सुधारकर सरकार भरोसा फिर मजबूत कर सकती है

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल केवल एक चिकित्सा संस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लाखों मरीजों की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन हजारों मरीज दूर-दराज के गांवों और कस्बों से यहां इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के साथ सरकार की निशुल्क दवा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब इलाज के बाद डॉक्टर की लेखी दवाएं अस्पताल के काउंटर पर उपलब्ध नहीं होतीं तो मरीज और उसके परिजनों की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। हाल के दिनों में जीवनरक्षक दवाओं

सहित बड़ी संख्या में दवाओं की अनुपलब्धता की खबरें सामने आई हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

गरीब और मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहता है। निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदना हर परिवार के लिए आसान नहीं होता। विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए नियमित दवाएं जीवन का आधार होती हैं। यदि ऐसी दवाएं समय पर नहीं मिलें तो बीमारी बढ़ सकती है और आर्थिक बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि निशुल्क दवा योजना को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता

है।

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिन मरीजों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भेजा गया, कई दिनों बाद आने के लिए कहा गया या फिर बाहर से दवा खरीदने की सलाह दी गई, उनकी परेशानी को सहज रूप से समझा जा सकता है। जो मरीज सैकड़ों किलोमीटर दूर से किराया खर्च करके अस्पताल पहुंचता है, उसके लिए केवल दवा ही नहीं बल्कि दोबारा आने-जाने का खर्च भी बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे मरीजों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वह इलाज कराए या परिवार का खर्च चलाए।

यह भी सच है कि यह समस्या केवल जयपुर तक सीमित नहीं दिखाई देती। प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में समय-समय पर कुछ दवाओं की कमी



की शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं सप्लाई में देरी होती है तो कहीं खरीद प्रक्रिया पूरी होने तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। इससे सरकार की अच्छी योजनाओं की छवि प्रभावित होती है। जनता यह नहीं देखती कि कमी किस स्तर पर हुई है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अस्पताल पहुंचने पर दवा मिलनी चाहिए।

हालांकि इस पूरे विषय को केवल आलोचना के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने पिछले कई वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं

का उल्लेखनीय विस्तार किया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना जैसी पहल ने लाखों गरीब मरीजों को राहत दी है। यदि ये योजनाएं नहीं होतीं तो गरीब मरीजों का इलाज और भी कठिन हो जाता। इसलिए यह कहना उचित होगा कि योजना में कमी नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन के कुछ हिस्सों में सुधार की आवश्यकता है। अस्पताल प्रशासन का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दवाएं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उपलब्ध नहीं हो पाती तो स्थानीय स्तर पर खरीद की जाती है। कई बार आपूर्ति करने वाली कंपनियों की ओर से विलंब होने के कारण अस्थायी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि वास्तव में ऐसा है तो

इसका समाधान भी प्रशासनिक स्तर पर संभव है। दवाओं की उपलब्धता का नियमित आकलन, समय रहते नई खरीद प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था से इस प्रकार की कठिनाइयों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं। राजस्थान इस समस्या को केवल लापरवाही के रूप में नहीं देखता बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में देखता है। दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और कई बार अनुमान से अधिक मरीज आने के कारण स्टॉक जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस समस्या को केवल लापरवाही के रूप में नहीं देना भी पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन और दवा आपूर्ति एजेंसियां मिलकर ऐसी व्यवस्था

विकसित करें जिससे आवश्यक दवाओं का भंडार हमेशा सुरक्षित रहे तकनीक का बेहतर उपयोग भी इस दिशा में बड़ा समाधान बन सकता है। यदि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं का ऑनलाइन स्टॉक रियल टाइम अपडेट हो तो यह पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में बची है और कब नई खेप की आवश्यकता होगी। इससे आपूर्ति में होने वाली देरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। मरीजों को भी मोबाइल या हेल्पलाइन के माध्यम से यह जानकारी मिल सके कि संबंधित दवा किस अस्पताल में उपलब्ध है। इससे उन्हें अनावश्यक चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के साथ संवाद की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। यदि किसी दवा की अस्थायी कमी है।



लोन के नाम पर 43 शिक्षकों से करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़

3 महीने की जांच के बाद अंतरजिला गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप और चेकबुक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद

कोडमांगव। जिले के फरसगांव और केशकाल थाना क्षेत्र में शिक्षकों को विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक अंतरजिला संगठित गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। करीब तीन महीने तक चली तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद पुलिस ने गिरोह के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार अब तक इस गिरोह ने 43 शिक्षकों को अपना शिकार बनाया है और उनसे करीब 10 से 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। हालांकि कुछ पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि बदनामी और सामाजिक संकोच के कारण कई लोग अब भी सामने नहीं आए हैं। उनका दावा है कि जिले में 150 से 200 शिक्षक इस तरह की ठगी का शिकार हो सकते हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब फरसगांव निवासी संजय कोडोपी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्हें और उनके साथियों को विभिन्न बैंकों से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर करीब दो करोड़ रुपये की ठगी की गई।

इसी तरह बड़ेडोंगर निवासी अनंत कुमार निर्मलकर ने करीब चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं केशकाल क्षेत्र के देवेन्द्र किशोर खवास, योगेश्वर बैद्य सहित अन्य शिक्षकों ने भी करोड़ों रुपये की ठगी की रिपोर्ट पुलिस को दी। जांच में

सामने आया कि आरोपी लंबे समय से संगठित तरीके से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। गिरोह पहले शिक्षकों से संपर्क करता और कम समय में कई बैंकों से बड़ी राशि का पर्सनल लोन दिलाने का भरोसा देता। इसके बाद बैंक कर्मचारियों और लोन एजेंटों के माध्यम से अलग-अलग बैंकों में लोन आवेदन करवाए जाते। लोन स्वीकृत होने के बाद शिक्षकों को केवल 40 प्रतिशत राशि दी जाती, जबकि शेष 60 प्रतिशत रकम आरोपियों और उनके सहयोगियों के विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली जाती थी। आरोपी पीड़ितों को भरोसा दिलाते थे कि दो से तीन वर्षों के भीतर पूरा लोन, व्याज और एचआरए सहित चुका दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद आरोपी रकम लेकर फरार हो जाते थे और पूरा कर्ज शिक्षकों के सिर पर छोड़ देते थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने कई मामलों में फर्जी आधार कार्ड और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। कई शिक्षकों के पते में बदलाव कर नकली आधार कार्ड बनवाए गए और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग बैंकों से लोन स्वीकृत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा (आईपीएस) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में एसडीओपी फरसगांव अभिनव उपाध्याय और एसडीओपी केशकाल अरुण नेताम के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ितों और आरोपियों के बैंक खातों का विस्तृत विश्लेषण किया। मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई।

सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र किसड़ी में बंद हैंडपंप की हुई मरम्मत

ग्राम कुर्मीपाली में नलकूप खनन कर पेयजल का किया स्थायी समाधान

महासमुंद। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण की दिशा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए ग्राम किसड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र में बंद पड़े हैंडपंप की मरम्मत कर उसे पुनः चालू कर दिया गया है। वहीं ग्राम कुर्मीपाली के बाजारपारा में नलकूप खनन का कार्य सफलपूर्वक किया गया है।

विकासखंड सरायपाली के ग्राम किसड़ी निवासी श्री यशपाल पटेल ने आवेदक क्रमांक 26144597500087 के माध्यम से ग्राम किसड़ी के उप स्वास्थ्य केन्द्र में बंद पड़े हैंडपंप की मरम्मत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

आवेदन प्राप्त होते ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए



आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। विभाग के तकनीकी दल द्वारा स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य किया गया तथा 30 मई 2026 को हैंडपंप की मरम्मत पूर्ण कर उसे पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। इससे मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और ग्रामीणों को पुनः स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

मांग के सफल निराकरण के पश्चात आवेदक श्री यशपाल पटेल को इसकी सूचना भी प्रदान कर दी गई। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी तरह ग्राम कुर्मीपाली के निवासी श्री उपेन्द्र बारिया ने

जीपीएम में आज भी बैगा समुदाय की नहीं सुधरी स्थिति

गौरैला पेंड्रा मरवाही। दूरस्थ बैगा बहुल गांवों में स्वच्छ पेयजल को लेकर आज भी हालात नहीं बदले हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के परिवार पीने के साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों को निस्तारी के साथ-साथ पीने के लिए भी कुएं और ढोढ़ी के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गौरैला विकासखंड के राजमेरगढ़ के छोटकी दादर क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संचालित पेयजल टंकियां स्थापित की गई हैं, लेकिन बोरवेल में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से इनका संचालन नियमित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कई परिवारों को एक से डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित टंकी तक पहुंचकर पानी भरना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों को पानी मिलने के लिए एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां प्राकृतिक जल स्रोत का विस्तृत विश्लेषण किया। मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई।



और गंभीर हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल कनेक्शन तो पहुंचा दिए गए, लेकिन अधिकांश नलों में लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपये की योजना का लाभ कागजों तक सीमित नजर आ रहा है। गौरैला विकासखंड के साल्हेघोरी, बेन्दरापानी और छिंदपानी गांवों में भी स्थिति कबोबेश यही है। यहां रहने वाले बैगा परिवार आज भी कुएं और ढोढ़ी के पानी से ही अपनी दैनिक जरूरतों के साथ पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घरों में लगे नल कई महीनों से बंद पड़े हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। साल 2025 में गौरैला विकासखंड के साल्हेघोरी, बेन्दरापानी और छिंदपानी क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप महामारी का रूप ले चुका है। उल्टी-दस्त से कुछ बैगा

आदिवासियों की मौत भी हुई थी। उस समय स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में शिविर लगाकर उपचार किया था और पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था भी की गई थी। इसके बावजूद एक साल बाद भी स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

अधिकारियों का कहना है कि राजमेरगढ़ पहाड़ी एरिया है, इस वजह से जल स्रोत में दूषित जाती है। जिन गांवों में डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, उन गांवों के प्राकृतिक जल स्रोतों में हमने दवाएँ का छिड़काव कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस साल भी संबंधित विभाग पेयजल स्रोतों में क्लोरीन डालने तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित रखे हुए है, जबकि नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है।

आवेदन क्रमांक 26144603800008 के माध्यम से ग्राम कुर्मीपाली के बाजारपारा में बोर खनन कराने का अनुरोध किया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बिना विलंब आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की और स्थल का तकनीकी परीक्षण कराया। जांच के उपरांत 2 जून 2026 को रिंग मशीन के माध्यम से 120 मीटर गहराई तक नलकूप खनन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। नलकूप खनन पूर्ण होने से बाजारपारा के निवासियों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि इससे पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। समयबद्ध कार्रवाई के लिए उन्होंने शासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से परिवार को मिला 2 लाख की बीमा राशि



महासमुंद। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना द्वारा समय पर प्रदान की गई आर्थिक सहायता परिवार के लिए कठिन समय में आर्थिक संबल सिद्ध हुई तथा दैनिक आवश्यकताओं एवं अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में सहायक बनी। घोडारी निवासी स्वर्गीय श्रीमती सतरूपा चक्रधारी के निधन उपरांत उनके नामित उत्तराधिकारी श्री पवन चक्रधारी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 02 लाख रुपए की बीमा राशि बैंक ऑफ बड़ौदा, मेन ब्रांच, महासमुंद के माध्यम से आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई। उक्त बीमा राशि का दावा स्वीकृत कराने एवं लाभ परिवार तक पहुँचाने में जिला अग्रणी बैंक, महासमुंद के प्रबंधक श्री

प्रकाश चन्द्र मेहर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मेन ब्रांच, महासमुंद के शाखा प्रबंधक श्री संदीप कुमार साव, बैंक अधिकारी श्री अभिषेक भारती तथा एफएलसी के श्री ओम प्रकाश पटेल का सहयोग एवं मार्गदर्शन रहा। इनके संयुक्त प्रयासों से मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सका।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जीवन बीमा किसी भी परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण

नशे में टल्ली मिले हेडमास्टर: स्कूल के बाहर जमीन पर लेटकर की गाली-गलौज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से शिक्षा के मांदर को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतिहास

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला रामानुजगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम शाल्ही के खोरखोरीपारा प्राथमिक स्कूल का है। यहां पदस्थ हेडमास्टर हरिनंदन सिंह स्कूल के समय में शराब के नशे में इतने धुत थे कि वे खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा



सकता है कि हेडमास्टर नशे की हालत में जमीन पर लेटे हुए हैं और लगातार गाली-गलौज कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है।

आखिरकार भिलाई निगम आयुक्त राजीव पांडेय का हुआ तबादला, एआईएस सुरुचि सिंह संभालेंगी कामकाज

भिलाईनगर। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के विरुद्ध महापौर नीरज पाल और कांग्रेस पार्षदों की मुहिम का नतीजा सामने आ गया है।

राजीव पांडेय का ट्रांसफर अपर संचालक. उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर किया गया है। भिलाई निगम आयुक्त और महापौर नीरजपाल के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी।

महापौर ने उनको यहां से हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया था। हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन ट्रांसफर आदेश को वे अपनी जीत मान सकते हैं। जारी हुआ ट्रांसफर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है, जिसमें राजीव कुमार की जगह वर्तमान में राजनांदगांव जिला पंचायत सीईओ 2020 बैच की आईएएस अधिकारी सुरुचि सिंह को

आयुक्त नियुक्त किया गया है। 8 जून 1996 को भिलाई नगर निगम का गठन हुआ था। अब तक यहाँ 26 आयुक्त रहे हैं। 27वें आयुक्त के रूप में सुरुचि सिंह पहली महिला आयुक्त के तौर पर पदभार संभालेंगी। उनके सामने भिलाई निगम में वेतन संकट, आवसय योजना और राजस्व वसूली जैसे कई अहम मुद्दे चुनौती के तौर पर होंगे।

हत्या मामले में एक नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार

गरियाबंद। आकाश कश्यप हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने युवक पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैनुवर पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई को आकाश कश्यप की संदिग्ध मौत के मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय परीक्षण और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि युवक की मौत गंभीर मारपीट के कारण हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या में तब्दील कर संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सामूहिक रूप से मारपीट करना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो लकड़ी के डंडे भी बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में देवकुमार निषाद (20), भीखम यादव (18), मनीष यादव (19), लकी नेताम (19), लोकेश यादव (23) और डिगेंद्र निर्मलकर (18) को गिरफ्तार किया है।

कोर्ट ने महिला और उसके प्रेमी को सुनाई उम्रकैद की सजा

रायगढ़। रायगढ़ जिले में एक महिला ने अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए कथित प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुमाने से दंडित किया है। यह घटना 12 फरवरी 2020 को हुई थी। मृतक विश्वेश्वर राठिया के भाई विन्देश्वर राठिया ने धरमजयगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि विश्वेश्वर अपनी पत्नी सहोदरा राठिया और बच्चे के साथ पुराने मकान में सो रहा था। रात करीब 2.30 बजे सहोदरा ने नए मकान में आकर बताया कि विश्वेश्वर कहीं बाहर से गिरकर आया है और उसे चोट लगी है। विश्वेश्वर को धरमजयगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह 5 बजे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की जानकारी मिलने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी टीकाराम उर्फ बन सागर राठिया का सहोदरा राठिया के साथ अवैध संबंध था। टीकाराम अक्सर उनके घर आता-जाता था।

2200 किमी की साइकिल यात्रा पर निकले मनेंद्रगढ़ के दो युवा

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। आस्था, साहस और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम पेश करते हुए मनेन्द्रगढ़ के दो युवा रामनारायण केवट और दुर्गेश गिरी साइकिल यात्रा पर निकले हैं। लगभग 2200 किलोमीटर की नगे पांव साइकिल यात्रा पर दोनों भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, साइकिल चलाने को लेकर लोगों को जागरूक करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का जनजागरण अभियान भी है। बुधवार को दोनों युवाओं ने यात्रा शुरू करने से पहले मनेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धबाबा धाम, श्रीराम मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत करते हुए सफल एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। रामनारायण केवट ने बताया कि यह उनकी तीसरी धार्मिक एवं प्रेरणादायक यात्रा है। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2024 में अयोध्या तक 19 दिनों की पैदल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी।

पेंड्रा-कोटमी मार्ग पर कोयले से भरा ट्रेलर नदी में गिरा

जीपीएम। पेंड्रा-कोटमी मुख्य मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खुन्जी नदी की पुलिया पर कोयले से भरा एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। राहत की बात यह रही कि ट्रेलर में सवार चालक और परिचालक को केवल मामूली चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर कोयला लेकर पेंड्रा की ओर जा रहा था। खुन्जी नदी की पुलिया पर पहुंचते ही चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। तेज गति के कारण ट्रेलर पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरा। दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल चालक एवं परिचालक को बाहर निकालने में मदद की। घटना की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों का हाल जाना। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार और वाहन से नियंत्रण खोना हादसे की वजह माना जा रहा है।

नए स्कूल भवन का निर्माण अब तक नहीं हुआ पूरा

मोहला-मानपुर। जिले में शाला भवनों का अभाव बदहाल शिक्षा व्यवस्था का बड़ा कारण बना हुआ है। जिला प्रशासन की कमजोरी और शिक्षा विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इस ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य जिले में शिक्षा व्यवस्था का इस कदर बेड़ागर्क कर रखा है कि नौनिहालों की तालीम खुले रंग मंच और छोटे-छोटे सामुदायिक भवनों में सिमट कर रह गई है। वहीं जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि तमाशबीन बने हुए हैं। विडंबना ही कहे कि जिप में शिक्षा समिति के सभापति और क्षेत्र में सतरूढ़ भाजपा के जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र औंधी में सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब है। औंधी तहसील अंतर्गत ग्राम आलकन्हार में बीते 5 वर्षों से एक खुले रंगमंच में शाला लग रही है। इसी तरह 4 से 5 वर्ष बीतने को है ग्राम मार्चुल व घोडाझरी तथा ग्राम हुरेली में महज एक कमरा वाले छोटे-छोटे गुमटीनुमा सामुदायिक भवन में शाला संचालन हो रहा है। इसी इलाके के ग्राम बालेर में तो शिक्षा व्यवस्था का स्तर इस कदर गिरा दिया गया है।

स्कूल जतन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी %स्कूल जतन योजना% में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए शासन ने 100 करोड़ की भारी भरकम राशि जारी की थी। दावे था कि अब बच्चों को सर्वसुविधायुक्त और सुरक्षित माहौल मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों की जुगलबंदी ने मासूमों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है। स्कूल जतन योजना के अंतर्गत मरम्मत किए गए 50 से अधिक स्कूल अब भी जर्जर है और योजना में हुए भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। ताजा मामला बेमेतरा



नगरपालिका अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 7 के नवीन प्राथमिक शाला से सामने आया है। सत्र 2022-23 में महज दो साल पहले जिस स्कूल भवन की मरम्मत पर लाखों रुपए बहाए गए थे, उसकी छत का प्लास्टर अब भरभरा कर गिरने लगा है।

स्कूल शिक्षिका ने बताया कि पहले कक्षाओं में प्लास्टर गिर रहा था, जिसके बाद सुरक्षा के नाते बच्चों को हॉल में बिठया गया। लेकिन लापरवाही की हद देखिए, अब हॉल की छत से भी कंक्रीट के बड़े-बड़े टुकड़े टूटने लगे हैं। एक बड़े हादसे के डर से स्कूल

प्रबंधन ने आनन-फानन में बच्चों की छुट्टी कर दी है। इसाथ ही दुर्घटना की लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी और नगरपालिका को भेज दी गई है। वहीं दूसरा मामला बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा के ग्राम भनसूली के स्कूल का है। जहां मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 96 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष बनाया गया है। जो हैंडओवर से पहले ही जर्जर हो गया, जिसे देखते हुए शाला प्रबंधन ने हैंड ओवर से इनकार कर दिया है। कंक्रीट गिरते देख

सहमे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए बेमेतरा नगरपालिका ने आनन-फानन में एक अस्थायी व्यवस्था की है। अब इस प्राथमिक शाला के बच्चों की कक्षाएं %सिंधी धर्मशाला% में लगाई जा रही हैं। यह स्थिति प्रशासन के उन तमाम विकास के दावों की पोल खोलती है, जो कागजों पर चमक रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद जर्जर भवनों का मामला तूल पकड़ते ही बेमेतरा जिला प्रशासन बैंकफुट पर है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगौड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी निर्माण एजेंसियों और संबंधित विभागों की आपात बैठक बुलाई है।

नगर पंचायत झगराखांड में पेयजल संकट गहराया, पार्षदों ने सीएमओ पर फोड़ा टीकरा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। नगर पंचायत झगराखांड इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है।इंटेकके की मोटर खराब होने से कॉलोनी वासियों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। गर्मी और बढ़ती पानी की जरूरत के बीच लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं, जबकि जिम्मेदारों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में हैरानी की बात ये है कि सत्ता पक्ष के ही पार्षद अब अपनी ही नगर पंचायत के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद देवनारायण सिंह और वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद सुनील मिश्रा ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेन्द्र पात्रे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारियों की हठधर्मिता, उदासीन रवैये और निर्णय लेने में देरी के कारण नगर की मूलभूत व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। उनका आरोप है कि कई बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई-



सुनील मिश्रा ,पार्षद वार्ड 04 दूसरी ओर मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेन्द्र पात्रे ने सभी आरोपों को निरे से खारिज कर दिया है।उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ पार्षद नियमों के विरुद्ध कार्य कराने का दबाव बना रहे हैं। सरकारी खरीदी केवल तद्रूपोर्टल के माध्यम से ही की जा सकती है और विना निर्धारित प्रक्रिया के कोई भी खरीद करना नियमों के खिलाफ है। यदि नियमों की अनदेखी कर खरीदी की जाती है तो ऑडिट में गंभीर आपत्तियां आती हैं और इसकी जवाबदेही अधिकारियों को उठानी पड़ती है।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में अब 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2027-28 से छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र का संचालन अब प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रोत सिंह ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में संचालित होने वाले 16 जून से 30 अप्रैल के शिक्षा सत्र को अब समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि, छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है; 01 मई से 15 जून तक का ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही यथावत रहेगा। इस नए बदलाव को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने कड़े निर्देश दिए हैं। अब से हर साल 01 अप्रैल को सत्र शुरू होने के साथ ही शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकलों का वितरण, स्कूली गणवेश (यूनिफॉर्म) का वितरण, अन्य सभी छात्रहितैषी योजनाएं और गतिविधियां अनिवार्य रूप से प्रारंभ कर दी जाएंगी।

छत्तीसगढ़ में अब कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित

रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रोत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बच्चों के फाउंडेशनल स्टेज को मजबूत करने और प्राथमिक स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए संबंधित शैक्षणिक सत्र के 01 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के लिए आयु सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है। नर्सरी (बालवाटिका-1)- 3 वर्ष से अधिक एवं 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार केजी-1 (बालवाटिका-2)- 4 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से कम, केजी-2 (बालवाटिका-3)- 5 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम, कक्षा पहली में- 6 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होनी चाहिए।

रविशंकर सागर बांध के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 4.58 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा धमतरी जिले के विकासखण्ड-धमतरी के महानदी परियोजना समूह अंतर्गत रविशंकर सागर बांध सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्वास कार्य के लिए 4 करोड़ 58 लाख 12 हजार रुपये स्वीकृत किये हैं। योजना के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित

रायपुर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया है। यह पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा दिया है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक, कांकेर ने बताया कि इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक आवेदक भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल <https://awards.gov.in/> पर 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। कांकेर जिला प्रशासन ने जिले के पात्र व्यक्तियों, संस्थाओं और नागरिकों से निर्धारित समयावधि में इसके लिए नामांकन करने की अपील की है।

हरी खाद से खेत होंगे उपजाऊ, बढ़ेंगी पैदावार और कम होंगी लागत

रायपुर। कृषि की बढ़ती लागत और मृदा की घटती उर्वरता के बीच हरी खाद किसानों के लिए एक प्रभावी, प्राकृतिक और किफायती विकल्प बनकर उभर रही है। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के प्राध्यापकों एवं वैज्ञानिकों ने किसानों से हरी खाद एवं हरी पत्तियों की खाद का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील करते हुए बताया कि इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, रासायनिक उर्वकों पर निर्भरता घटती है तथा फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि हरी खाद के लिए ढ़ैंचा, सनई, मृंग, उड़द, लोबिया एवं ग्वार जैसी दलहनी फसलें बोई जाती हैं। इन फसलों को बुवाई के लगभग 35 से 45 दिन बाद, फूल आने से पहले रोपावैटर अथवा कल्टीवेटर की सहायता से खेत में ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। कुछ दिनों में यह सड़कर जैविक खाद का रूप ले लेती हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है।

लोकार्पण के कुछ दिन बाद नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज में आई दरारें

विधानसभा अध्यक्ष रमन ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, उच्च स्तरीय जांच की मांग

रायपुर। जिले में हाल ही में निर्मित तीन रेलवे ओवरब्रिजों में दरारें आने के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और निर्माण में लापरवाही बरतने वाले सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

डॉ. रमन सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि हाल ही में हुई बारिश के बाद राजनांदगांव जिले के बरगा, आलीवारा और मुसरा स्थित नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिजों में गंभीर क्षति सामने आई है। उनका कहना है कि लोकार्पण के कुछ ही दिनों के भीतर पुलों में आई दरारें निर्माण गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

उन्होंने बताया कि दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन के नागपुर मंडल अंतर्गत डोंगरगढ़-राजनांदगांव रेलखंड पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत लगभग 26 करोड़ रुपये



की लागत से इन रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण कराया गया था। इनका लोकार्पण जून 2026 में किया गया था। इसके कुछ दिन बाद 4 और 5 जुलाई को जिले में हुई बारिश के बाद ओवरब्रिजों में करीब 60 से 70 फीट लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें दिखाई दीं। इन दरारों के कारण पुलों की सुरक्षा पर सवाल उठ गए हैं और फिलहाल इन्हें आवागमन के लिहाज से असुरक्षित माना जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक निर्माण का लोकार्पण होने के कुछ ही दिनों बाद इस तरह क्षतिग्रस्त हो जाना अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस घटना को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों में भी नाराजगी

और नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

अपने पत्र में डॉ. रमन सिंह ने रेल मंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई

जाए और ओवरब्रिज निर्माण से जुड़ी एजेंसी, ठेकेदार, परामर्शदाता तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रभावित ओवरब्रिजों का तत्काल सुरक्षा परीक्षण कराने, आवश्यक मरम्मत अथवा ज़रूरत पड़ने पर पुनर्निर्माण सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है, ताकि भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके।

डॉ. रमन सिंह ने उम्मीद जताई है कि जनहित और सार्वजनिक धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय इस मामले में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करेगा।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

बी. टेक- पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रारंभ

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु बी. टेक- (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी. टेक - (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

प्रवेश प्रक्रिया पी.ई.टी.-2026, जेईई और मेन्स - 2026 तथा 12वीं (गणित समूह) की प्रावीण्य सूची के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम-2026 के अनुसार संपन्न की जाएगी। ऑनलाइन काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन दिनांक 10 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 (रात्रि 11:00 बजे तक) उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में



ऑनलाइन पंजीयन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पंजीकृत अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची 23 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसके उपरांत निर्धारित कार्यक्रमानुसार 24 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक विभिन्न चरणों में पी.ई.टी. 2026, जेईई और मेन्स -

2026 तथा 12वीं (गणित समूह) के आधार पर सीट आवंटन, दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। प्रवेश विज्ञापन, ऑनलाइन काउंसिलिंग समय-सारणी, ऑनलाइन पंजीयन दिशा-निर्देश, ऑनलाइन काउंसिलिंग दिशा-निर्देश, सीटों का विवरण एवं अन्य आवश्यक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://igkv.ac.in> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पूर्व सभी दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा नवीनतम जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।

कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी

17 जुलाई तक भेजे गए ईओडब्ल्यू रिमांड पर

रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब, कस्टम मिलिंग और कोल लेवी घोटाला में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। वकीलों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायधीश सुमित कापूर ने अग्रवाल को 17 जुलाई तक के लिए ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया है। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि नियत अवधि तक पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू फिर से उन्हें कोर्ट में पेश करेगी।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब, कोल

से वे बीते तीन सालों से फरार चल रहे थे। ईओडब्ल्यू के साथ-साथ ईडी भी उनकी तलाश कर रही थी।

बता दें कि कस्टम मिलिंग घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को बुधवार को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल कांग्रेस होने के साथ-साथय नान के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुचर्चित घोटालों में आरोपी बनाए जाने के बाद

कार्यकर्ताओं को डॉ. रमन सिंह की नसीहत, कहा चुनाव में अब ढाई साल ही शेष, पद नहीं, संगठन के लिए करें काम

कवर्धा। भाजपा जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि ढाई साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिसने प्रदेश को बदनाम कर दिया था। अब ऐसी सरकार को दोबारा प्रदेश में नहीं आने देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के भी ढाई साल पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ ढाई साल का कार्यकाल शेष है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन और सरकार के लिए पूरी ताकत से काम करना होगा।

डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट कहा



कि प्रदेश में जितने भी संगठनात्मक और राजनीतिक पद थे, सभी भर चुके हैं। अब कोई पद खाली नहीं है, इसलिए रोना-धोना या मनमुटाव रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी समय आने पर ज़रूरत के अनुसार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती है और सभी को अवसर मिलता है।

डॉ. रमन सिंह ने अपने 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने कभी किसी पद की मांग नहीं की। यहां के कार्यकर्ता इसे अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर काम करने और पार्टी नेतृत्व के निर्णयों पर विश्वास बनाए रखने की अपील की।

दो माह के भीतर ही हटे जीपीएम के कलेक्टर संतोष, विजय दयाराम होंगे नये कलेक्टर

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के 5 आईएसएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में सबसे बड़ी गाज गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन पर गिरी है, जिन्हें महज दो महीने के भीतर ही उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। विजय दयाराम के., भा.प्र.से. (2015), संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य कौशल विकास अभिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है।

श्री हेमंत रमेश नंदनवार, भा.प्र.से. (2020), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री हेमंत रमेश नंदनवार, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वैतन) नियम, 2016 के नियम-12 के के तहत संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

श्री सुमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (2021),



आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य शहरी विकास अभिकरण के पद पर पदस्थ करता है। सुमित अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य शहरी विकास अभिकरण का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री रिमिजियुस एक्का, भा.प्र.से. (2011), संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य शहरी विकास अभिकरण केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य शहरी विकास अभिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

श्री सुमित अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य शहरी विकास अभिकरण का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वैतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य शहरी विकास अभिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

मुख्यमंत्री कैप कार्यालय की पहल से प्रेमनगर की लो-वोल्टेज समस्या का हुआ समाधान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में संचालित मुख्यमंत्री कैप कार्यालय की त्वरित पहल से जशपुर जिले के पथलगांव स्थित प्रेमनगर मोहल्ले में लंबे समय से बनी लो-वोल्टेज की समस्या का समाधान कर दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार, प्रेमनगर के रहवासियों ने मुख्यमंत्री कैप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर बताया था कि पूरे मोहल्ले में केवल एक ट्रांसफार्मर होने के कारण पिछले कई दिनों से लगातार लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई थी। इसके चलते घरों में लगे विद्युत उपकरण सुचारू रूप से संचालित नहीं

हो पा रहे थे। वहीं, कुओं और बोरवेल की मोटरें भी नहीं चलने से पेयजल संकट गहरा गया था और लोगों को दैनिक उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

मुख्यमंत्री कैप कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बदलते हुए नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया। इसके बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई और लो-वोल्टेज की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई।

समस्या के त्वरित समाधान पर प्रेमनगर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा मुख्यमंत्री कैप कार्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया।

खरीफ सीजन में खेती किसानों ने पकड़ी गति

रायपुर। प्रदेश में खेती-किसानी का काम तेजी के साथ जारी है। राज्य में अब तक 20.14 लाख से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मृंग, मृंगफली, रामतिल सहित विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 41 प्रतिशत है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सफलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं।

उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने की भी कहा हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 7.78 लाख मीट्रिक टन खाद और 3.62 लाख क्विटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है।

कांग्रेस नेता रामगोपाल की गिरफ्तारी भाजपा का राजनैतिक षड्यंत्र : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की ऐसीबी, ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई गिरफ्तारी भाजपा सरकार का राजनैतिक षड्यंत्र है। विधानसभा चुनाव के समय से ही भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करती रही है। पहले केंद्रीय एजेंसियों को इस काम में लगाया गया अब राज्य की जांच एजेंसी के माध्यम से षड्यंत्र किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी को लगाकर कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर परेशान करती रही है। जिन मामलों में ईडी जांच करके कुछ हासिल नहीं कर पाई उसी में ईओडब्ल्यू से जांच करवाई जा रही है। यह मामला अदालत में नहीं टिकेगा अदालत में भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब होगा। पूरी मजबूती से इस षड्यंत्र के खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जाएगी। हम भाजपा के इन षड्यंत्रों को

जनता के बीच बेनकाब भी करेगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नकटी में गरीबो का मकान तोड़ने के बाद सरकार कहती है, वहां विधायक आवास नहीं बनायाजायेगा। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव, मंत्री केदार कश्यप पत्रकारवातां लेकर कहते है कि वहां पर विधायको के लिये मकान बनाने का कोई योजना नहीं है। आज ओपी चौधरी का भी बयान आया है वहां विधायक आवास नहीं बनाया जायेगा। अक्टूबर 2024 में आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद कलेक्टर को पत्र लिखकर षष्ठम विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु नकटी में अतिक्रमण भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये कहा था। इस पत्र में आयुक्त छ.ग. गृह निर्माण मंडल के पत्र क्र. 58 दिनांक 25.09.2024 का हवाला भी दिया है। यह पत्र बताता है कि भाजपा नेताओं को हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने अपनी सरकार की गलती छुपाने झूठ बोला है। विधानसभा में राज्यस् मंत्री टंकराम वर्मा जब



भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे, उस समय उनको बताते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्पष्ट किया कि नकटी गांव में विधायकों के लिये आवास हेतु जगह चिह्नोक्त है।। गरीबों का आशियाना उजाड़ने के बाद सरकार सफाई दे रही है। सरकार को अनर की गलती का अहसास हो गया है तो वहीं पर तोड़े गये मकान फिर बनाये जाये तथा प्रभावितो को मुआवजा दिया जाये। कौन रजनीश चंद्राकर, नितिन अग्रवाल, तथा कौन मंत्री है जिसको फायदा पहुंचाने नकटी के मकान तोड़े?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पद्म विभूषण, भूषण तिजन बाई छत्तीसगढ़ की शान थी, अभिमान थी, उनके दुखद निधन के बाद राज्य में राजकीय शोक किया जाना था। भाजपा सरकार ने उनके निधन पर राजकीय शोक नहीं घोषित किया। छत्तीसगढ़ के जनता इस सरकार के निर्णय से आहत है। तिजन बाई पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण तीनों ही सम्मान से सम्मानित होने वाली बिरला व्यक्तित्व थी एवं छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पहचान थी। सरकार ने प्रदेश की महान विभूति का उनके अंतिम समय पर उचित सम्मान नहीं किया।

थीडी उद्योग दुर्घटना प्रबंधन के साथ सरकार की भी आपराधिक लापरवाही

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि उरला के थ्रीडी फैक्ट्री में ब्लास्ट से 3 मजदूरो की मौत, बड़ी संख्या में मजदूरो के घायल होना दुखद है। मैं मृतकों के और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह हादसा उद्योग प्रबंधन के साथ सरकार की भी

आपराधिक लापरवाही। भाजपा के कुशासन में औद्योगिक हादसों में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस मामले में अनेको लोगों के झुलसकर घायल होने की सूचना है, मृतकों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है। घायलों के बेहतर इलाज की समुचित व्यवस्था कर न्यायिक जांच कराई जाए और मृतकों के परिवार को एक-एक करोड़ और घायलों को 50-50 लाख मुआवजा दे। ढाई साल में प्रदेश के औद्योगिक दुर्घटनाओं में 300 से अधिक मजदूरो की जान गयी है। भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, कुछ महीना पहले सकी जिले में डभरा थाना क्षेत्र के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 24 मजदूरों की मौत एवं 50 से अधिक मजदूरों के घायल हुये थे, तथा गोदावरी प्लांट (रायपुर) में भट्टी विस्फोट और स्वदेश मेटालिक प्लांट (बलौदाबाजार) में 30 फीट की ऊँचाई से गिरकर श्रमिक की मौत सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाते हैं।

क्या किंग मेकर से किंग बनने की ओर प्रशांत किशोर?

शैलेश कुमार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसफ विजय की जीत के रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद पहली बार चुनाव मैदान में उतर गए हैं। वह बिहार के बांकीपुर से विधानसभा का उप चुनाव लड़ेंगे। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई है। तमिलनाडु में चमत्कारी ढंग से विजय की पार्टी टी.वी.के. की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने खूब वाहवाही लुटी। वैसे इस तरह का चमत्कार पहले भी वह बंगाल, बिहार, पंजाब और कई अन्य राज्यों में दिखा चुके हैं। उनकी रणनीति को क्षेत्रीय पार्टियों की जीत की गारंटी माना जाता है लेकिन उनकी अपनी जन सुराज पार्टी का रिकार्ड कुछ अच्छा नहीं रहा। 2025 में उनकी पार्टी बड़े जोशो-खरोश के साथ पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरी और बुरी तरह पराजित हुई। प्रशांत अब उप चुनाव में कौन कोई कमाल दिखा पाएंगे ? बांकीपुर उप चुनाव में प्रशांत किशोर के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प जरूर हो गया है। करीब 30 वर्षों से इस सीट पर नितिन नबीन परिवार का कब्जा रहा है। नितिन नबीन 5 बार और उनसे पहले उनके पिता 4 बार इस क्षेत्र से जीत चुके हैं। भाजपा ने इस बार एक नए चेहरे अभिषेक कुमार को मैदान में उतारने की घोषणा की है। अभिषेक कुमार कायस्थ हैं और नितिन नबीन के करीबी माने जाते हैं। वह भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं। राजद ने अपनी पुरानी उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता को फिर टिकट दिया है, जो 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थीं। 2025 के चुनाव में भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को इस क्षेत्र में 98,299 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर लगभग 62.66 प्रतिशत था। रेखा कुमारी 46,363 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। लेकिन प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार बंदना कुमारी को सिर्फ 7,717 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर लगभग 4.9 प्रतिशत था। ऐसे में चर्चा हो रही है कि जन सुराज के लिए अत्यंत कमजोर साबित सीट पर प्रशांत किशोर खुद को दांव पर क्यों लगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हार के बाद प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य हाशिए पर जा चुका है। ऐसे में खुद को प्रसंगिक बनाए रखना प्रशांत की सबसे बड़ी चुनौती है। बांकीपुर, जिसका नाम पहले पटना वैस्ट था, बिहार की राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कहते हैं कि इस सीट से जीतने वाले के लिए पर ताज जरूर सजता है। नितिन नबीन इस सीट से विधायक बने। उसी से उनके भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता खुला। 1962 में इस सीट से कांग्रेस के कृष्ण बल्लभ सहाय जीते और बाद में मुख्यमंत्री बने। 1967 में इसी सीट से महामाया प्रसाद सिन्हा जीते और मुख्यमंत्री बने। 1977 में इस सीट पर भाजपा के ठाकुर प्रसाद जीते, बाद में उन्हें राज्य में मंत्री बनने का मौका मिला। वह भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं और उनके बेटे रविशंकर प्रसाद को भी केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला। इस सीट पर कायस्थों का बोल-बाला रहा है। अनुमान है कि इस क्षेत्र में कायस्थ करीब 13 प्रतिशत के आसपास हैं लेकिन राजपूत 8 प्रतिशत, भूमिहार 7 प्रतिशत, ब्राह्मण 5 प्रतिशत मिलाकर सवर्ण आबादी करीब 35 प्रतिशत हो जाती है। 1995 के बाद से भाजपा की जीत में सवर्ण मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। दलित आबादी करीब 8 प्रतिशत, मुस्लिम 8 प्रतिशत और यादव 12 प्रतिशत हैं (करीब 30 प्रतिशत)। इसलिए आजकल मुकाबला भाजपा और राजद के बीच ही होता है। कुल मतदाता करीब 3.80 लाख हैं लेकिन 2025 के चुनाव में 1 लाख 55 हजार, यानी लगभग 41 प्रतिशत ने ही मतदान किया।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यदि शतायुर्वै पुरुषः इत्यादि श्रुति के अनुसार अवश्य ही मनुष्य की आयुः अधिक से अधिक सो वर्ष ही होती है तब तो यह बात प्रत्यक्ष के भो सर्वथा प्रतिकूल सिद्ध हो जायेगी। इसलिये हमें लोकरूढ़ि को छोड़कर वेदोक्त शत और सहस्र शब्द का अर्थ वैदिक-कोश में ही ढूढना चाहिये, तथा जिन मन्त्रों में उक्त दोनों शब्द प्रयुक्त हुये हों उन सबका समन्वय करके ही इन शब्दों का वास्तविक अर्थ ह्रदयङ्गम करना चाहिये। अस्तु, वेदार्थनिर्णायक सर्वमान्य निरुक्त-निष्पटु में उन्त दोनों शब्दों का अर्थ बहुत बहुत लिखा है यथा-

बहु नामान्युत्तराणि द्वादश -

उरुः, तुविः, पुरुः, भूरिः, शशत्, विश्वम्, परीणसा व्यानशिः, शतम्, सहस्रम्, सलिलम्, कुविद।

(निरुक्त अध्याय 3 खण्ड 13)

अर्थात् - उरु, तुवि, आदि बारह बहुत शब्द के

पर्याय हैं। इसी तरह वेद के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय प० मधुसूदन जी ओझा (जयपुर) ने अपने वैदिक-कोश में लिखा है कि--

उरु पुरु शशद् विश्वं, परीणसा व्यानशिः कुवित्सलिलम्।

तुवि च शतं च सहस्र, भूरि च बहुवाचका एते।।

(वैदिक-कोश पुष्ठ 14)

उपर्युक्त दोनों प्रमाणों से स्पष्ट है कि वेद में शत और सहस्र इन दोनों शब्दों का गौण अर्थ तो चाहे प्रसंगङ्गवश सो और हजार भी होता हो परन्तु इनका वास्तविक सर्वसम्मत एवं मुख्य अर्थ तो सर्वत्र बहुत ही होगा। निरुक्त के प्रसिद्ध भाष्यकार श्रीदुर्गाचार्य जी ने अपनी निरुक्त टीका में उक्त उरु आदि शब्दों के वेदोक्त उदाहरण भी दिये हैं, जिनमें कि इन शब्दों के प्रयोगों द्वारा ही इनका बहुत्व पर्याय होना सिद्ध किया है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

भारत की एक्ट ईस्ट नीति का नया अध्याय

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्वक स्तरपर भारतीय पीएम की 6 से 11 जुलाई 2026 तक की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की छह दिवसीय यात्रा जिसपर भारत से पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई हैं,केवल तीन देशों का राजनयिक दौरा नहीं है, बल्कि यह भारत की लगभग एक दशक से अधिक समय से विकसित हो रही एक्ट ईस्ट नीति का सबसे परिपक्व और व्यापक स्वरूप है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हिंद- प्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था,समुद्री व्यापार, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सामरिक संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, विश्व की लगभग आधी आबादी, वैश्विक जीडीपी का बड़ा हिस्सा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार काअधिकांश भाग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में मैं यह मानता हूँ कि भारत का इस क्षेत्र में सक्रिय,संतुलित और बहु आयामी नेतृत्व केवल उसकी विदेश नीति का विस्तार नहीं बल्कि उसकी वैश्विक भूमिका का पुनर्परिभाषण भी है। यही कारण है कि इस यात्रा को एक्ट ईस्ट नीति के एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।यह यात्रा केवल एक नियमित विदेश दौरा नहीं है, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें भारत स्वयं को हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के एक उत्तरदायी, विश्वसनीय और निर्णायक साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है।जिसपर भारत से पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति, मुक्त, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक,समुद्री सुरक्षाव्यापार प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों, आपूर्ति श्रृंखला और लोगों के बीच संबंधों को नई गति देना है। इस दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय वार्ता, व्यापारिक समुदाय से संवाद और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संपर्क कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

साथियों, आज विश्व की भू-राजनीति का केंद्र तेजी से हिंद -प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रहा है। वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जबकि ऊर्जा आपूर्ति,डिजिटल कनेक्टिविटी और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क भी इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। ऐसे समय में भारत का उद्देश्य केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है,बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत करना भी है जिसमें अंतरराष्ट्रीय



कानून,नौवहन की स्वतंत्रता और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान बना रहे। यही कारण है कि इस यात्रा को अनेक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ 2026 की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलों में से एक मान रहे हैं।भारत की एक्ट ईस्ट नीति अब केवल दक्षिण- पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित नहीं रही। यह आर्थिक,सामरिक,तकनीकी और समुद्री साझेदारी का व्यापक ढांचा बन चुकी है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस रणनीति के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

साथियों, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम-बहुल लोकतंत्र है और मलका जलडमरूमध्य के निकट उसकी रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है।ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत सुरक्षा का प्रमुख भागीदार है, जबकि न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, कृषि, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं।इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक आयाम चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।भारत ने कहीं भी प्रत्यक्ष टकराव की नीति नहीं अपनाई है,लेकिन वह नियम- आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संतुलित शक्ति संरचना का समर्थन करता है। दक्षिण चीन सागर, समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर भारत समान विचार वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा किसी सैन्य गठबंधन का संदेश नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, संतुलन और साझेदारी का संकेत है।भारत और इंडोनेशिया के संबंध इस यात्रा में

राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस



किसानों, एक्काउद्यमियों (एक्का फार्मिंग क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों) और मछुआ बंधुओं

द्वारा किए गए योगदान की सराहना करना है और हमारे मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए टिकाऊ तरीकों पर सामूहिक रूप से सोचने और चर्चा करने के लिए एक वातावरण बनाना है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मत्स्य प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान देने में मदद किसानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को

स्वीकार करने का एक अहम मंच है। यह आधुनिक एकुआकल्चर तकनीकों को अपनाने, मत्स्य उत्पादकता में सुधार और जलीय संसाधनों के संरक्षण में उनके समर्पण और नवाचार पर प्रकाश डालता है। पिछले कुछ वर्षों में, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेपों के कारण मत्स्य पालन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है।

भारत सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में समग्र रूप से परिवर्तन लाने और देश में नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक उत्थान और समृद्धि लाने में हमेशा अग्रसर रही है। इस क्षेत्र ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, घरेलू मत्स्य की खपत और निर्यात व्यापार में वृद्धि, अपशिष्ट को कम करने की परिकल्पना की जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए ।

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में लगभग 55 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। पीएमएणएसवाई सतत वृद्धि और विकास पर बल देकर मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तन लाने और लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए तत्पर है। यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र की भागीदारी, उद्यमशीलता में वृद्धि, व्यवसाय मॉडल के विकास, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने, नवाचारों और पहलों के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हुए मत्स्य पालन और एकुआकल्चर में नवीनतम नवाचारों जैसे स्टार्ट-अप, इनक्यूबेटर, आदि को शामिल करने पर भी जोर देता है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र की अतिथि-आधारित अभियानों की स्मृति में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मना रहा है।

आज का इतिहास

- 1890 व्योमिंग 44 वें अमेरिकी राज्य के रूप में स्थापित किया गया।
- 1912 थॉमस मेकेन्ज़ी के इस्तीफे के बाद, विलियम मासी न्यूजीलैंड के 19 वें प्रधानमंत्री बने।
- 1913 यूरोपीय देश रोमानिया ने बुल्गारिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1921 आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटिश बलों के बीच एक संघर्ष के एक दिन बाद, सोलह मृतकों में बेलफास्ट्सल में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हिंसा।
- 1924 डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाया।
- 1936 फ्रांसीसी सोशियल पार्टी की स्थापना हुई।
- 1938 हावर्ड ह्यूज ने 91 घंटे विमान उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया था।
- 1940 जर्मन लूपूटवार्फ़ ने ब्रिटेन के युद्धक्षेत्र में ब्रिटेन के युद्ध शुरू करने के लिए ब्रिटिश काफिले पर हमले शुरू किए।
- 1941 गैर-यहूदी जातीय ध्रुवों के समूह के निकट क्षेत्र के पास के होलोकास्ट-ए समूह ने पोलैंड के जेदवाबैन के सैंकड़ों यहूदियों की हत्या कर दी।
- 1943 अमेरिका, ब्रिटिश और कनाडाई सेना ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिसली द्वीप पर हमला किया।
- 1947 चीन के कैंटोन क्षेत्र में नदी में रेलगाडी गिरने से 200 लोगों की मौत हुई।
- 1956 ब्रिटिश हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स ने मौत की सजा को खत्म किया।
- 1958 ब्रिटेन में पहले पाकिंग मोटर स्थापित किया गया।
- 1962 टेलस्टार , दुनिया का पहला सक्रिय, प्रत्यक्ष रिलेक्टेक्शन उपग्रह, नासा द्वारा एक डेल्टा रॉकेटफ्रेम केप केनावेरल में लॉन्च किया गया था।
- 1966 मार्टिन लूथर किंग, जूनियर ने शिकागो स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में एक रैली का नेतृत्व किया, जो उत्तरी अमेरिका के सबसे महत्वाकांक्षी नागरिक अधिकारों के अभियानों में से एक है।
- 1967 उरुग्वे बर्न सम्मेलन सिंधि का सदस्य बन गया। सिंधि का वास्तविक नाम बर्न सम्मेलन कॉपीराइट सिंधि है।
- 1967 दशमलव मुद्रा को न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया था। दशमलव मुद्रा एक प्रकार की मुद्रा है जिसमें उप इकाइयाँ होती हैं।
- 1973 राष्ट्रमंडल में राष्ट्रों के भीतर बहामा को पूर्ण आजादी मिली।
- 1973 जॉन ऑयल मैनेट जे पॉलेग्रेटी के पोते जॉन पॉल ग्रेटी III का रोम में अपहरण कर लिया गया था।
- 1976 इटली में सीवसो आपदा हुई। 3, 7, 8 – टेटाक्लोरोडिबेंजो-पी-डाइऑक्सिन के रिसाव के कारण ऐसा हुआ।

बिहार में बदलाव की बयार, जाति-धर्म तोड़ न्याय के लिए एक हुआ समाज

उमेश चतुर्वेदी

जाति और धर्म के बिना आज राजनीति की कल्पना बेमानी है, लेकिन बिहार में जातिवाद का असर कुछ ज्यादा ही दिखता है। यहां मानस किस कदर जातिवाद के घेरे में है, इसे समझने के लिए किसी खास जाति के अपराधियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को देखना होगा। तब उस अपराधी के जाति विशेष द्वारा उसे बेकसूर बताने और कार्रवाई को जातिवादी बदला बताने की होड़ लग जाती है। लेकिन इसी बिहार में हाल ही में हुई एक घटना की प्रतिक्रिया में उभरा जनाक्रोश इसके ठीक उलट है। इसमें जाति और धर्म की सीमाएं टूट गई हैं। भोजपुर पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए सवर्ण युवक भरत तिवारी के इंसाफ के लिए उतरे लोगों के बीच कोई जातीय दीवार नजर नहीं आ रही। हालांकि इसे भी जातीय रंग देने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ उसी दलित समाज के स्त्री और पुरुष मैदान में उतर आए, जिनकी रहनुमाई का दावा करने वाली राजनीति हस्ती ने यह रंग देने का प्रयास किया था।

इससे इनकार नहीं कि भारतीय समाज में ऊंच-नीच का भाव रहा है। फिर भी समाज में सद्भाव, सहयोग और मेलजोल की गहरी परंपरा है। सामाजिक मामलों में कई बार जाति की दीवारें टूटती भी नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव और राजनीति का मसला सामने

आता है, जातीय सोच पूरी ताकत से उभर आती है। बिहार इस मामले में कुछ ज्यादा ही बदनाम है। ऐसे माहौल में अगर सवर्ण समुदाय के भरत तिवारी की पुलिस के हाथों हुई हत्या के खिलाफ सड़कों पर दलित और पिछड़े समुदाय तक के लोग उतर आएं तो मानना पड़ेगा कि पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का जीन अब भी देश की रगों में बह रहा है। बस उसे जगाने की जरूरत है। हालांकि भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ को भी जातीय रंग देने की कोशिश भी हुई। हैरत की बात है कि इसके पीछे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नजर आए। जातिवादी चश्मे से इस घटना को देखते हुए उन्होंने कह दिया कि भरत तिवारी चूंकि ब्राह्मण था, इसीलिए सवर्ण समाज आक्रोशित है। उसकी जगह कोई दलित और पिछड़ा होता तो इस मामले को इतना तूल नहीं दिया जाता। मांझी के इस बयान ने जातिवादी खोल से बाहर निकले जनाक्रोश की आग में घी का काम किया। विरोध में भरत के गांव बिलौटी ही नहीं, आसपड़ोस के दलित और पिछड़े परिवार भी गुस्से से भर उठे। गंगा के कटान से प्रभावित ये लोग मांझी की लानत-मलामत में उतर आए। उन्होंने उल्टे मांझी से ही पूछ लिया कि हमारे नेता होने के बावजूद उन्होंने उनकी हालत जानने की कोशिश क्यों नहीं की। लोगों का कहा था कि जिसके खिलाफ वे बोल रहे हैं, साधनहीन होने



की बजाय वही व्यक्ति उनके साथ खड़ा रहा। इतिहास

बिहार में ठीक साढ़े इक्कीस साल पहले इसी तरह जाति और धर्म का बंधन टूटा था। झारखंड के अलग होने के बाद राज्य में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा था। इसी दौरान बारह जनवरी 2005 को पटना के पटेल नगर से दिनदहाड़े पंद्रह साल के किसलय का अपहरण कर लिया गया। इस अपहरण के खिलाफ तब बिहार का पूरा समाज उतर आया था। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान तब जन-जन की जुबान पर चढ़ गया था। उन्होंने कहा था, मेरा किसलय लौटा दो। किसलय की वापसी का सवाल जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ समूचे बिहार की आवाज बन गया था। भोजपुर जिले के

बिलौटी गांव के भरत तिवारी की कथित मुठभेड़ में हत्या के बाद एक बार फिर बिहार का समाज ठीक उसी तरह जाति और समुदाय के खांचों को तोड़ सत्य और न्याय के साथ खड़ा नजर आ रहा है।

भोजपुर जिले का जवानिया गांव गंगा के ठीक किनारे है। इस गांव को पिछले साल गंगा की लहरों ने तकरीबन लील लिया। कटान से प्रभावित लोगों को अपने घर-खेत गंवाना पड़ा, तब से ज्यादातर लोगों की स्थिति बदहाल है। प्रभावितों को घर के लिए जमीन और पैसे तो दिए गए, लेकिन जो जगह उन्हें मिली, वह गड़े वाली है। बाकी सहूलियतें भी ना के बराबर मिली हैं। इनकी बस्ती में हाल के दिनों तक पानी का चापाकल तक नहीं थे, कुछ थे भी तो उनमें पानी नहीं आ रहा था। इन्हें बदहाल लोगों की आवाज बनकर भरत तिवारी सक्रिय थे। भरत तिवारी के न रहने के बाद बिलौटी और जवानिया के उजड़े लोगों का कहना है कि उन्हें भरत तिवारी की ही वजह से थोड़ी-बहुत सुविधाएं मिली हैं। इनके लिए वे ही प्रशासन से लड़ते रहे। कटान पीड़ित जवानिया गांव वालों का दर्द है कि उन्हें पानी से निकालकर फिर से पानी में ही बसा दिया गया है। उन्हें डर

तीन पड़ाव, एक संदेश: हिंद-प्रशांत में बढ़ती भारत की कूटनीतिक ताकत

देवेश त्रिपाठी

ऐसे समय में, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता छोटे और मझोले देशों को नए रणनीतिक साझेदार तलाशने के लिए प्रेरित कर रही है और पश्चिम एशियाई संकट के मद्देनजर वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाओं के नए समीकरण आकार ले रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा इस पूरे क्षेत्र में भारत को एक निर्णायक, विश्वसनीय और संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिहाज से बेहद अहम है। दरअसल, पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब वह बहुआयामी कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए हिंद-प्रशांत से लेकर यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक अपने रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ आसियान का सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य भी है। पश्चिम एशिया में जारी संकट ने दुनिया को यह दिखाया है कि समुद्री व्यापारिक मार्ग सामरिक दृष्टि से कितने अहम हो सकते हैं। इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट मलक्का जलसंधि के बिल्कुल मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया का करीब चालीस फीसदी समुद्री व्यापार और चीन का 80 प्रतिशत से अधिक आयात गुजरता है। ऐसे समय में, जब चीन पाकिस्तान के

ग्वادر, श्रीलंका के हंबनटोटा और म्यांमार के बंदरगाहों के विकास में सहभागी बना हुआ है, भारत का इंडोनेशिया के साथ समुद्री सहयोग अहम हो जाता है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच हुए अन्य समझौतों के साथ फिलीपीन और वियतनाम के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया तीसरा देश भी बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्तों को देखें, तो दोनों देश क्राड के सदस्य हैं और मुक्त, समावेशी तथा नियम-आधारित हिंद-प्रशांत व्यवस्था के समर्थक हैं। रक्षा अभ्यासों से लेकर खुफिया सहयोग, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज और स्वच्छ ऊर्जा तक दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अब कोशिश एक संतुलित समग्र आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को अंतिम रूप देने की होगी। न्यूजीलैंड अपेक्षया छोटी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन हिंद-प्रशांत की बदलती रणनीति में उसका बड़ा महत्व है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के कुछ महीनों बाद हो रही यह यात्रा 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जब सभी देश सहयोग के विकल्प तलाश रहे हैं, तब भरोसेमंद साझेदारियां अहम हो जाती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि वह साझा समृद्धि का सबसे विश्वसनीय साझेदार बनने की क्षमता रखता है।

छोटे से अस्त्र से साउथ चाइना सी में ड्रैगन का गेम हुआ ओवर

अभिनव आकाश

इतिहास गवाह है कि दुश्मन की घेराबंदी वहीं करनी चाहिए जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता की धरती से चीन की दुखती रथ पर हाथ रख दिया। जब दुनिया की नजरे पीपुम मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोबो की मुलाकात पर थी तब बंद कमरे में एक ऐसी डील फाइनल हो रही थी जिसने बीजिंग के रक्षा एक्सपर्टों के पसीने छुड़ा दिए। इंडोनेशिया ने अब भारत को उस अस्त्र मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मारक क्षमता का लोहा पाकिस्तान में घुसकर मनवाया। जकार्ता में मंगलवार को जो कुछ हुआ वो डिफेंस दो देशों की मुलाकात नहीं थी बल्कि एक नए डिफेंस सुपर पावर का उदय था। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रोबोबो के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल की हो रही है। भारत ने ना केवल इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दी बल्कि अब अपनी सबसे आधुनिक अस्त्र मिसाइल भी सौंप दी है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने इंडोनेशिया के जरिए चीन की घेराबंदी पूरी कर ली है।

अस्त्र एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को तब तबाह कर देती है जब वो पायलट की आंखों को दिखाई भी नहीं देता है। 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और सुपरसोनिक रफ्तार इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की श्रेणी में खड़ा करता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका युद्ध का अनुभव यानी कि बैटल प्रोवेन होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपनी जिस ताकत का प्रदर्शन किया उसमें इन मिसाइलों की भूमिका ने दुनिया भर को चौंका दिया। इंडोनेशिया अच्छे से जानता है कि अगर उसे चीन के आधुनिक सुखोई और जे सीरीज के विमानों का मुकाबला करना है तो उसे भारत के अस्त्र की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए अब यह एमओयू साइन हो गया।

दोनों नेताओं ने सबांग पोर्ट को मिलकर विकसित करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। यह पोर्ट इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित है, जहाँ से मलक्का जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ मलक्का) दिखाई देता है और यह भारत के आने वाले



ग्रेट निकोबार ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। चूंकि सबांग पोर्ट मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित होगा, इसलिए भारत के लिए मलक्का जलडमरूमध्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जहाँ से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। दरअसल, यह संकरा मार्ग विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता है, जो वैश्विक व्यापार मात्रा का 25–35 प्रतिशत है, और चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 80 प्रतिशत इसी पर निर्भर करता है। इससे भारत को हिंद महासागर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) नौसेना की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखने की क्षमता भी मिलेगी, जहां वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। द डिप्लोमैट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सबांग पोर्ट भारतीय नौसेना को पूर्वी हिंद महासागर और मलक्का जलडमरूमध्य में ऑपरेशन जारी रखने के लिए एक अच्छी जगह पर स्थित लॉजिस्टिक्स और री-सप्लाई नोड देगा। खास तौर पर, सबांग का पोर्ट मानवीय आपात स्थितियों में मदद करने, आपदा राहत पहुंचाने और समुद्री लुटेरों के खिलाफ गश्त करने की भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सबांग भारत को समुद्र में बेहतर पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा, यह गहरे पानी वाला पोर्ट पनडुब्बियों सहित सभी तरह के नौसैनिक जहाजों को संभालने में सक्षम है।

मोदी और प्राबोबो की बातचीत का एक अहम नतीजा मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ एमओयू था। भारत ने इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रयर-अर्थ परमानेंट मैनेट बनाने की सुविधाओं में निवेश करने के लिए समझौता किया है, क्योंकि नई

दिल्ली स्प्लाइ चैन में विविधता लाना चाहती है।

भारत की निकेल में खास दिलचस्पी है, जो ईवी बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों का एक अहम हिस्सा है। यह भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वह साफ ऊर्जा वाली तकनीकों की ओर बढ़ना चाहता है। अभी, भारत अपने फेरोनिकेल का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इंडोनेशिया से आयात करता है, जो स्टील बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल मिनरल्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के रिफाईंड निकेल में इंडोनेशिया और चीन की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत थी, और अकेले इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 2040 तक 44 प्रतिशत होने का अनुमान है।

दोनों देशों ने चुनाव में सहयोग के लिए एक एमओयू पर भी साइन किया है। इस समझौते के तहत, नई दिल्ली जकार्ता को कस्टमाइज़्ड इलेक्ट्रॉनिक मोर्टिंग मशीनें (ईवीएम) उपलब्ध कराएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया, दोनों की साझा ताकत रही है। हम दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू के जरिए अपने लोकतांत्रिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता चुनाव टेक्नोलॉजी, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और बेहتریन तौर-तरीकों के आदान-प्रदान में सहयोग को बढ़ाएगा। खबरों के मुताबिक, भारत जिन ईवीएम को तैयार करेगा, उन्हें जकार्ता 2029 के आम चुनावों में इस्तेमाल करेगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र अभी भी पेपर बैलेट का इस्तेमाल करके चुनाव कराता है।

इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से उस जगह बैठा है जहां से चीन का व्यापारिक और सैन्य रास्ता गुजरता है। अगर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स भारत की अस्त्र मिसाइल से लैस हो जाते हैं तो चीन की वायु सेना के लिए इस इलाके में घुसपैठ करना सुसाइड मिशन यानी आत्मघाती जैसा होगा। ब्रह्मोस के बाद अब बात अस्त्र की करें तो भारत ने पहले ब्रह्मोस देकर इंडोनेशिया की नौसेना को मजबूत किया, एमओयू साइन किया और अब अस्त्र देकर उसकी वायुसेना को अजब बना दिया है। यह पीपुम मोदी का वो डबल अटैक है जिसने चीन के स्टिंग ऑफ पल्स के जवाब में भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड्स तैयार कर लिया है।



अवसरवादी नेताओं का बोलबाला है।

प्रतिबद्धता से लोग कन्नौ काटने लगे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार केवल ममता बनर्जी के लिए ही सबक नहीं है। अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए भी इसमें सख्त संदेश छिपा है कि लोकतंत्र से भटकने का क्या अंजाम उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वैयक्तिक विरोध की सियासत का अब कोई अर्थ नहीं रहा है।

ममता बनर्जी से बेहतर कौन समझेगा कि जब वे सत्ता में थीं तो उन्होंने हमेशा उस राजनीतिक दल से दूरी बनाए रखी, जिसकी कोख में उनकी वैचारिक सोच परिपक्व हुई थी। वे विश्व की सबसे पुरानी पार्टी के नए नेतृत्व से चिढ़ती रहीं लेकिन अपने ही भतीजे को दल में उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करती रहीं। अनेक मौकों पर उन्होंने कांग्रेस और उसके नए खून को यूपीए का मुखिया मानने से इनकार किया।

यह अजीब रवैया था कि जिस दल के लगभग 100 सांसद हों, उसके अस्तित्व को ही वे नकारने पर तुली थीं। एक बार तो एनसीपी के सुप्रियो शरद पवार के साथ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग किया था। ममता बनर्जी का व्यक्तित्व और स्वभाव धीरे-धीरे विरोधाभासी होता गया है।

वे अपने भाषणों में बार-बार लोकतंत्र की दुहाई देती

थीं, मगर खुद एक अधिनायक से कम नहीं थीं। लोकतंत्र कभी भी किसी तानाशाह को पसंद नहीं करता। प्रादेशिक पार्टियों का यही दोहरा चरित्र है। वे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव या तो कराते नहीं या फिर औपचारिकता ही निभाते हैं। उनका अध्यक्ष राजा की तरह बरताव करता है।

एनसीपी को भी अपने इसी चरित्र के कारण नुकसान उठाना पड़ा। लोकतंत्र सामूहिक नेतृत्व की बात करता है। उसमें पार्टी की दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को भी उभरने का भरपूर अवसर मिलता है। एनसीपी के टुकड़े हुए तो उसका बड़ा कारण भी यही रहा। कोई सत्ताधारी दल अपने सामने प्रतिपक्ष को मजबूत क्यों होने देना चाहेगा?

वह तो विपक्षी पार्टियों को निरंतर कमजोर करने के प्रयास करता रहेगा। ऐसे में यदि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रादेशिक दल अपने-अपने घर मजबूत रखें तो सत्ता पक्ष को अवसर ही नहीं मिलेगा। घर भारत में बीते तीन-चार दशक से यह नहीं हो रहा है। जब एनसीपी बिखरी तो ममता बनर्जी ने सबक नहीं लिया। जब शिवसेना के टुकड़े हुए तब भी ममता बनर्जी ने अपना घर ठीक नहीं किया।

घर ठीक करने की बात तो दूर, प्रतिपक्षी खेमे में टूट-फूट के विरोध में भी चुप्पी साधे रहीं। आरजेडी में भी अब यही प्रयास चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी खामोश बैठी है। जब उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसमें विभाजन करने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। तब अखिलेश यादव बेबस होकर पार्टी में टूट देखते रहेंगे।

असल में अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय लोकतंत्र वैचारिक आधार पर दो ध्रुवों में बंट चुका है। एक तरफ दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी ओर कांग्रेस और उसके साथ वैचारिक सहानुभूति रखने वाले दल। दोनों तरफ लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाए रखने की चुनौती है। अधिनायकवादी दैत्य कमोबेश सारी पार्टियों को निगल रहा है। सियासी दलों को अब यह सत्य स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

तीन दशक का गतिरोध खत्म, यमुना समझौते से खुले नए अवसर

केएस तोमर

तीन दशकों तक राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना के पानी के बंटवारे का प्रस्ताव राजनीतिक मतभेदों के कारण अटक रहा। लेकिन, हाल ही में हुए ऐतिहासिक समझौते ने यह गतिरोध खत्म कर दिया। राज्यों के बीच नदी विवादों के दौर में यह समझौता सहकारी संघवाद और ठोस नीतिगत कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा।

राजस्थान के लिए यह समझौता रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। राज्य का लगभग दो-तिहाई हिस्सा सूखे और अर्ध-सूखे इलाकों में आता है, जहां बारिश बहुत अनियमित होती है। कई जिलों में जमीन के नीचे से पानी निकालने का काम खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जबकि बार-बार पड़ने वाले सूखे से खेती और ग्रामीण लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है। यमुना का पानी कई इलाकों में पीने के पानी की उपलब्धता को बढ़ा सकता है और भूजल भंडार पर निर्भरता को कम कर सकता है। बेहतर सिंचिका से ज्यादा मूल्य वाली फसलों, बागवानी और डेयरी विकास को बढ़ावा मिल सकता है और किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है। इसके अलावा, पानी की कमी वाले जिलों में औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है। शहरी इलाकों में पानी की सुरक्षा बेहतर हो सकती है, जिससे आर्थिक विस्तार में मदद मिलेगी। पानी की बेहतर उपलब्धता से पर्यटन को भी फायदा मिल सकता है।

यह समझौता मौजूदा व्यवस्थाओं के तहत आवंटित जल वितरण में एक प्रमुख ऊपरी तटीय राज्य के रूप में हरियाणा की भूमिका को भी सुदृढ़ करता है। परियोजना से जुड़े अवसररचना विकास से हरियाणा के भीतर नहर नेटवर्क को मजबूती मिलने की संभावना है। साथ ही निर्माण के दौरान रोजगार भी सृजित होगा। लंबे समय से लंबित नहर कार्यों के पूरा होने से जल प्रबंधन दक्षता में सुधार हो सकता है, संचरण हानि कम हो सकती है और सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण हो सकता है। जल वितरण के बेहतर नियमन से कई जिलों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.4 करोड़ हेक्टेयर है, फिर भी इसके बहुत कम हिस्से में ही भरोसेमंद

सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर ही निर्भर है। अतिरिक्त पानी मिलने से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। पानी की बेहतर उपलब्धता से पशुपालन तथा राज्य के कुछ हिस्सों में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर को भी फायदा होगा, जिससे भविष्य में निवेश करना और अधिक फायदेमंद हो सकेगा।

हालांकि, इस समझौते में कई चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। आवश्यक नहर अवसररचना के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता होगी। भूमि अधिग्रहण से मुआवजे संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर स्थानीय विरोध उत्पन्न हो सकता है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों से परियोजना के कुछ हिस्सों में देरी हो सकती है। नहर संरक्षण और जल परिवहन से संबंधित इंजीनियरिंग चुनौतियों से परियोजना के कुछ हिस्सों में देरी हो सकती है। नहर संरक्षण और जल परिवहन से संबंधित इंजीनियरिंग चुनौतियों के लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिए कठोर आवंटन सूत्रों के बजाय अनुकूल प्रबंधन की आवश्यकता है। इसलिए, प्रभावी निगरानी तंत्र अनिवार्य हो जाएंगे। निर्माण का पारदर्शी कार्यक्रम, नियमित प्रगति समीक्षा और अंतर-राज्यीय समन्वय समितियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रियाच्यवन एक बार फिर नौकरशाही विलंब का शिकार न हो। यह समझौता दिखाता है कि राजनीतिक सहमति, प्रशासनिक तालमेल और केंद्र की मदद से लंबी कानूनी लड़ाई के बिना बातचीत के जरिये समाधान निकाला जा सकता है। ऐसे उदाहरण भारत के संघीय ढांचे में भरोसा बढ़ाते हैं।

अगर निर्माण कार्य तय समय पर पूरा होता है, वित्तीय वादे पूरे किए जाते हैं और इसे लागू करते समय पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, तो यह प्रोजेक्ट लाखों लोगों के लिए पानी सुरक्षा को बेहतर बना सकता है। साथ ही, इससे खेती का उत्पादन, औद्योगिक विकास और ग्रामीण इलाकों में खुशहाली भी बढ़ सकती है। पर देरी, लागत का बढ़ना या प्रशासनिक लापरवाही पुरानी निराशाओं को फिर से जगा सकती है। इतिहास इस समझौते को उस पानी से परखेगा, जो आखिरकार उन खेतों और घरों तक पहुंचेगा, जिनके लिए यह वादा किया गया है।

गुरस्सा झट से हो जाएगा गायब,बस अपनाएं ये टिप्स



कहते हैं गुस्सा व्यक्ति को चंडाल बना देता है। बात-बात पर गुस्सा करने वाले इंसान से परिवार वाले और उसके आस-पास के लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार तो इस तरह के व्यक्ति से लोग बात करने से भी कतराते हैं। किसी परेशानी,तनाव,बिजनेस या नौकरी का परेशानी और रिश्तों में बढ रही दुरियां को कारण भी गुस्सा आने लगता है। कई बात तो इससे कुछ लोग खुद भी परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आप कुछ उपाय अपना कर इससे समस्या से राहत पा सकते हैं।

- गुस्सा आने पर किसी से बात करने की बजाए कुछ देर के लिए अकेले बैठ जाएं। मांसपेशियों को रिलैक्स करें। इससे गुस्सा शांत हो जाएगा।
- किसी बात से परेशान हैं तो गुस्सा होने की बजाए गहरी सांस भरे और आंखे बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करें।
- गुस्से को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि माहौल को खुशनुमा बनाएं। बढिया से परपन्मूय की महक लें। आप हैरान जाएंगे कि इससे गुस्सा खुशी में बदल जाएगा।
- ठंडा पानी पीने से भी गुस्सा शांत हो जाता है। परेशानी को दूर करने के लिए उल्टी गिनती गिनना शुरू करें।

कैंसर का इलाज करें खीरा, और भी कई बीमारियां में फायदेमंद



खीरा, इसे लोग सालाद के रूप में बड़े शौक से खाते हैं। सालाद के अलावा भी इसे सैंडविच या फास्ट में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। खीरा खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इससे शरीर में हमेशा ताजगी बनी रहती है। आइए जानते हैं इसके सेहत संबंधी फायदों के बारे में...

- कब्ज** : कब्ज होने पर खीरा खाने से पेट की परेशानी दूर होती है। इसे अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। रोजाना इसके सेवन से कब्ज से राहत पाई जा सकती है।
- ब्लड प्रेशर** : हाई ब्लडप्रेशर से राहत पाने के लिए खीरे का सेवन बहुत अच्छा होता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह शरीर को ठंडा रखता है।
- कैंसर** : इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से रोकथाम करने में मददगार हैं और यह बहुत अच्छा एन्टीऑक्सिडेंट भी है। जिससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
- वजन घटाएं** : खीरे में कैलोरी बहुत कम और फाइबर ज्यादा होता है। मीड डे की भूख को शांत करने के लिए खीरा खाएं। जिससे पेट देर तक भरा रहता है और वजन कम हो जाता है।
- किडनी** : खाने में हर रोज इसका इस्तेमाल करने से पथरी की परेशानी से बचा जा सकता है। यह पिते और कीडनी की पथरी से बचाए रखती है। खीरे के रस को दिन में 2-3 बार पीना लाभकारी होता है।
- कोलेस्ट्रॉल** : खीरे में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। दिल के मरीजों के लिए खीरा खाना बहुत अच्छा होता है। इसमें पाया जाने वाला स्टैरोल तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।
- पीरियड का दर्द दूर** : जिन लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान काफी परेशानी होती है वो दही में खीरे को कद्दूस करके उसमें पुदीना,काला नमक, काली मिर्च, जीरा और होंग डालकर खाएं। इससे काफी आराम मिलेगा।

कुछ इस तरह बनाएं अपनी सुबह खिली-खिली...



दी ब्याडी क्लाक गाइड टू बेटर हेल्थ के मुताबिक 10 में से महज 1 ही व्यक्ति सही मायनों में मायनो में मॉर्निंग पर्सन कहलाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10 में महज दो ही लोगों की स्थिति सुबह उठते हुए गंभीर होती है बाकी सब सामान्य रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी सुबह खिली-खिली हो, आप मॉर्निंग पर्सन कहलाएं तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अपना ध्यान देना होगा और सोने के घंटों में इजाफा कना होगा।

अच्छी नींद लें

डेलीबर्नडायकाम वेबसाइट के मुताबिक आपको चाहिए कि नियमित अच्छी नींद लें। अगर इसके लिए आपको अपने शिड्यूल में कुछ बदलाव करने होंगे तो उससे भी परहेज न करें। आप चाहें तो अपने काम को देर रात तक करने की बजाय देर शाम तक ही खत्म कर लें। अगर तब भी काम अधूरा रह जाए तो काम को वहीं अधूरा छोड़ सो जाएं और सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। रात को ली गई नींद आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जरूरी है। जब नींद पूरी होती है तो सुबह त 7के उठने से आपको परहेज भी नहीं होगा।

पर्याप्त समय लें

आप एक रात में किला फतह नहीं कर सकते। इसलिए यह न सोचें कि आप अपने शिड्यूल को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए बेहतर है कि आप पर्याप्त समय लें। धीरे-धीरे कर अपनी जीवनशैली में बदलाव करें। इतना ही नहीं संभव हो

साइकिल चलाने के ये फायदे

क्या कभी किसी ने बताए हैं आपको...



अगर आप वजन घटाने की सारी कोशिशें करके हार चुके हैं तो कुछ दिन साइकिल चलाकर देखें, अगर आपको फिट बॉडी की ख्वाहिश है तो साइकिल चलाना शुरू करें. साइकिलिंग से बेहतर शायद ही कोई दूसरी एक्सरसाइज हो. अगर आपको फिट और एक्टिव बॉडी चाहिए तो आज से ही साइकिल चलाना शुरू कर दें. जरूरी नहीं है कि आप साइकिल चलाने के लिए अलग से समय निकालें. आप चाहें तो

अपने रोजाना के कामों को पूरा करने के लिए ही साइकिल चला सकते हैं. ये छोटी सी कोशिश आपको व्यायाम जितना फायदा पहुंचाएगी. आप चाहें तो सुबह दूध लाने के लिए साइकिल चलाकर दुकान तक जा सकते हैं. हर रोज कुछ मिनट साइकिल चलाकर ही आप फिट और आकर्षक बॉडी पा सकते हैं. इसके अलावा भी साइकिल चलाने के कई फायदे हैं।

मानसून में करें इन साबुनों का इस्तेमाल, त्वचा में आएगा निखार

बारिश के मौसम में वातावरण में मौजूद नमी आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकती है, ऐसे में कुछ मामूली बदलाव और आयुर्वेदिक साबुन के इस्तेमाल से त्वचा की चमक व ताजगी बरकरार रखी जा सकती है. बायोटिक के सौंदर्य विशेषज्ञों और सोल फ्लॉवर के प्रबंध निदेशक शारदा ने मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल से संबंधित कुछ सुझाव दिए हैं.

- आयुर्वेदिक और हर्बल साबुन त्वचा के पीएच बैलेंस को प्रभावित किए बिना सौम्यता से शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं. इस मौसम में बैक्टीरिया और गंदगी से त्वचा को बचाना जरूरी है. ये साबुन त्वचा में नमी बरकरार रखते हैं और इसे रिजूविनेट करते हैं.
- आयुर्वेदिक साबुन जैसे बायो ऑलमंड ऑयल शरीर को पोषित करते हैं, जो प्राकृतिक पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं. वे बादाम, मारगोसा, नारियल तेल, हल्दी आदि से युक्त होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं.
- गुलाब के सत्वों से बना साबुन त्वचा में प्राकृतिक नमी बरकरार रखते हुए चमक और निखार लाता है. गुलाब का तेल और पंखुड़ियां त्वचा के दाग-धब्बों को दूर करते हैं.
- मानसून में लैवेंडर साबुन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके जीवाणुरोधी गुण त्वचा में हो रही जलन और खुजली को दूर करते हैं, इसकी खुशबू ताजगी और सुकून का अहसास कराती है.
- चारकोल साबुन तैलीय और मिश्रित त्वचा



के लिए मानसून में अच्छा विकल्प है. साबुन में मौजूद एक्टिवेटेड बैंबू चारकोल गंदगी, टॉक्सिन और अशुद्धियों को दूर कर त्वचा के रोम छिद्रों को खोल देते हैं. ये मुंहासे, दाग-धब्बे भी दूर करते हैं.

- पपीता और खीरा युक्त साबुन सभी

प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त होते हैं. यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटा कर रोम छिद्र खोल देता है और मुंहासों को नियंत्रित कर दाग-धब्बे कम करता है. इसके इस्तेमाल से त्वचा कोमल हो जाती है. यह त्वचा में नमी बरकरार रखता है.

इन चीजों से करेंगे साफ तो चमक जाएंगे सफेद जूते



सफेद जूते पर्सनेलिटी को भी चार चांद लगा देते हैं। आजकल वैसे भी इस रंग के जूतों का काफी ट्रेंड है लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस वजह से सफेद जूते पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ज्यादातर स्कूल के बच्चे और एक्सरसाइज करते समय लोग सफेद स्पोर्ट्सूज पहनते हैं लेकिन बारिश के दिनों में कीचड़ और मिट्टी की वजह से ये गंदे हो जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए कई लोग जूतों को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं लेकिन इससे जूते खराब हो जाते हैं और अच्छे से साफ भी नहीं होते। ऐसे में कुछ आसान तरीके अपनाकर इन्हें मिनटों में साफ किया जा सकता है।

- एक चम्मच बाइकार्बोनेट सोडा, आधा चम्मच पानी और आधा चम्मच हाईड्रोजन पEROक्साइड को एक बाउल में डालकर पेस्ट बना लें।
- अब जूतों के तस्मों को निकाल लें और टूथब्रश की मदद से इस पेस्ट को जूतों पर लगाएं। अब इन तस्मों को बाउल में डाल दें ताकि बचा हुआ पेस्ट उन पर लग जाए।
- पेस्ट लगे जूतों और तस्मों को 4-5 घंटों के लिए धूप में सूखने के लिए रख दें।
- जब जूतों का पेस्ट सूख जाए तो इन्हें ड्रिज़ेंट से धोएं और धूप में सूखने के लिए रख दें। इससे जूते एक दम चमक उठेंगे।

मानसून में ऐसे रखेंगे फर्नीचर का ध्यान तो नहीं होगा खराब

तेज तपती गर्मी के बाद मानसून का इंतजार तो हर किसी को बेसब्री से लगा रहता है। लेकिन जहां यह मौसम चेहरे पर मुस्कान लाता है, वहीं अपने साथ कई तरह की प्रॉब्लम भी लेकर आता है जैसे दीवारों की सीलन, कपड़ों में बदबू। इसके अलावा एक और चिंता है जो हर किसी को सताती है वो लकड़ी के फर्नीचर की क्योंकि इस मौसम में लकड़ी के फर्नीचर में सीलन और उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं लकड़ी फूलने लगती है ऐसे में घर का फर्नीचर खराब हो जाता है। फर्नीचर को बचाने के लिए लोगों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर आपको भी अपने फर्नीचर की चिंता सता रही है तो घबराएं नहीं। हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिससे आप लकड़ी के फर्नीचर को बचाएं रख सकती है।

- फर्नीचर को सेफ जगह पर रखें** : अपने घर में पड़े लकड़ी के फर्नीचर को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां, बारिश की बूंदें उनक तक न पहुंच पाएं। इससे वह गीले होने से बचे रहेंगे।
- समय-समय पर ऑयलिंग दें** : अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे भी लकड़ी के है तो उन्हें समय-समय पर ऑयलिंग करें। ऐसा करने से उम्रं कोई कीड़ा नहीं लगने पाएं।
- नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें** : घर में नमी को कंट्रोल करने के लिए सूखे नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ह्यूमीडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
- फर्नीचर को दीवारों से दूर रखें** : अधिकतर देखने को मिलता है कि लोग अपने फर्नीचर को दीवारों से जोड़कर रखते है लेकिन बारिस के मौसम में इनकी ख़ास केयर करनी पड़ती है। इसलिए बेहतर होगा की मानसून में लकड़ी को फर्नीचर को दीवारों से दूर लगाकर रखें। इससे वह डैम लगने से बचे रहेगे।
- पॉलिश या पेंट करवाएं** : बारसात के दिनों में अपने फर्नीचर को पॉलिश या पेंट करवाएं। इससे वह नमी से बचे रहें और खराब भी नहीं होंगे।



रेसिपी



विधि

मध्यम आंच पर एक पैन में सभी खड़े मसाले डालकर सुनहरा होने तक भून लें। गरम मसालों को प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। अब एक कड़ाही में तेल डालकर गर्म होने के लिए तेज आंच पर रखें। जब तक तेल गर्म हो रहा है। भूने साबुत मसालों को मिवसर में पीसकर पाउडर बना लें। तेल में काजू को डालकर हल्का सुनहरा होने तक तल लें। काजू को किचन पेपर में निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। काजू को एक बार में डालें फिर इसमें तैयार किया गर्म मसाला, चाट मसाला, काला नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह मिवर्स कर लें। आप चाहें तो बोझल को 9कवर करके अच्छी तरह हिला लें। तैयार मसालेदार काजू को सर्व करें या फिर एयरटाइट कंटेनर में डालकर हफ्ते 10 दिन तक रख सकते हैं।



विधि

एक कटोरे में मैदा, बटर और पानी ले कर मुलायम आटा गूंद लें। इसके बाद आटे को आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दें। तय समय के बाद इसे फिर से अच्छी तरह मसलें। जब यह मुलायम हो जाए तो इसकी छोटी-छोटी लोई लेकर पूड़ियां बेल लें। अब एक कटोरे में खोया, चीनी, तिल, घिसी नारियल, खसखस और कुछ बूंद वेनीला एसेंस की डालकर अच्छी तरह मिवर्स कर लें। तैयार मिश्रण से एक चम्मच मसाला पूरियों में रखें और इसे समोसे जैसा आकार दें। समोसे के कोनो को चिपकाने के लिए आप चाहें तो अंडे का इस्तेमाल करें या फिर कांटे वाले चम्मच से दबाकर एक कर सकते हैं इसके बाद जब समोसों में भरावन पूरी तरह से भर जाए तब इन पर बटर लगा दें। मीडियम आंच में एक कड़ाही में घी डालकर गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो समोसों को इसमें डीप फ्राई कर लें। आप चाहें तो इन समोसों को वाशनी में भी डिब्बो सकते हैं। इसके लिए 1 कप पानी में एक कप चानी डालकर वाशनी तैयार कर लें और फिर इन समोसों को इसमें डालकर कुछ देर तक रखें और निकालकर सर्व करें।

इथेनॉल प्रोडक्शन में मेरा बस 0.07% हिस्सा: गडकरी



नईदिल्ली।इथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी है। इंडिया टुडे टीवी से खास बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार की इस नीति का बचाव किया। गडकरी ने कहा कि इथेनॉल प्रोडक्शन में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.07 फीसदी है। इतनी कम हिस्सेदारी होने से उन्हें कोई निजी फायदा नहीं होता। अपने ऊपर लगे इन आरोपों को एक साजिश बताया। उन्होंने चुनौती भी दी कि अगर ई20 ईंधन से किसी पेट्रोल वाहन को नुकसान हुआ है, तो उसका सबूत सामने लाया जाए,इस खास बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को लेकर लगाए जा रहे निजी हितों के आरोप पूरी तरह गलत हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार का चीनी कारोबार सरकार की इथेनॉल नीति आने से पहले का है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इथेनॉल प्रोडक्शन में उनका सिर्फ 0.07 फीसदी हिस्सा है।

एआईआईएमएस पटना होगा और बड़ा, कैबिनेट की मुहर



पटना। बिहार सरकार की सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें स्वास्थ्य, परिवहन और मत्स्य पालन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल रहे। कैबिनेट ने पटना स्थित एआईआईएमएस के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा-भूसौला में 26.76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना पर लगभग 348.90 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि एआईआईएमएस पटना के विस्तार से सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को भी नई गति मिलेगी। इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया।

पंजाब में खुलकर सामने आई कांग्रेस की कलह

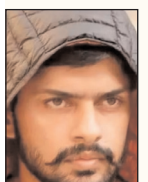


चंडीगढ़। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक नेताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल डेमेज कंट्रोल के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं, लेकिन चन्नी समर्थकों से उनकी मुलाकात अब तक नहीं हुई है।पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने मंगलवार को नेताओं के साथ मेल-मुलाकातें कीं, बैठकें कीं, लेकिन चन्नी समर्थकों ने इससे दूरी बनाए रखी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चन्नी के नाम का समर्थन कर रहे नेताओं ने बघेल से मुलाकात नहीं की है। इसे लेकर तरह-तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। इन सबके बीच अब अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग का बयान आया है।

शोपियां एनकाउंटर में मारा गया लश्कर का टॉप आतंकी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। चार दिन पहले शुरू हुए एनकाउंटर के बाद बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर जाकिर गनई का शव हथियार के साथ बरामद किया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में सच ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। शनिवार को दो आतंकवादी सीसीटीवी में दिखे थे और उसी दिन मुठभेड़ शुरू हुई थी। आखिरकार, चार दिन बाद शोपियां के चानपोरा गांव से मारे गए आतंकवादी का शव बरामद किया गया। अब यह कन्फर्म हो गया है कि शोपियां मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनाई मारा गया। आज शोपियां से उसका शव बरामद किया गया। शोपियां में मुठभेड़ के 4 दिन बाद मारे गए एक आतंकवादी का शव हथियार के साथ बरामद किया गया है। शनिवार को दो आतंकवादी सीसीटीवी में दिखे थे और उसी दिन मुठभेड़ शुरू हुई थी। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने रविवार को रात भर रुके रहने के बाद एक बड़ा आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन फिर से शुरू किया, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी घने बाग के अंदर छिपे हुए थे। ऑपरेशन का यह दूसरा दिन था।

लॉरेंस गैंग पर यूएस का शिकंजा, गोल्डी पर 50000 डॉलर का इनाम



नईदिल्ली। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यूएस, कनाडा और यूरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन हार्ड बॉल नाम के इस ऑपरेशन में उन नेटवर्कों को निशाना बनाया गया, जो कई अलग-अलग देशों में हत्या, जबरन वसूली, ड्रग तस्करी, अपहरण, हथियारों से जुड़े अपराध और दूसरे संगठित अपराधों में शामिल थे। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, अधिकारियों ने कई साल से चल रही जांच के तहत कैलिफोर्निया, इंडियाना, जॉर्जिया, कनाडा और स्पेन में 50 से ज्यादा सच वारंट पर कार्रवाई की और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इस मिली-जुली कार्रवाई का ऐलान करते हुए डीओजे ने बताया कि भारत में मौजूद तीन संगठित अपराध समूहों से जुड़े मामलों में तीन अलग-अलग संघीय अभियोगों के तहत 37 आरोपियों पर आरोप लगाए गए हैं। इनमें से 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 10 अभी भी फरार हैं।

ममता बनर्जी को झटका

टीएमसी के 440 करोड़ के बैंक डिपॉजिट फ्रीज

नई दिल्ली। जांच में अब तक यह सामने आया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को ट्रांसफर किए गए.

ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बैंक खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज कर दी है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि विमानन क्षेत्र में काम करने वाले केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े पांच परिसरों पर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई। यह कार्रवाई कथित तौर पर वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी, अवैध रूप से धन जुटाने और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध लेनदेन से जुड़े मामले में की गई। ईडी के अनुसार, इस बात की जांच कर रही है कि वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी, अवैध रूप से धन इकठ्ठा करने और संदिग्ध राशि को टीएमसी के कुछ बैंक खातों के माध्यम से कैसे भेजा गया। जांच में अब तक यह सामने आया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को ट्रांसफर किए गए.

केयरवेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने 2023 से 2026 के दौरान 82.96 करोड़



रुपये एक नई संबद्ध कंपनी को भेजे। इस धन का उपयोग एक एम्ब्रयर लेगेसी 600 विमान और एक अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया। जॉन एजेंसी के अनुसार, इन दोनों की खरीद पर करीब 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए, इसके अलावा, हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए 2023 में कैमैन आइलैंड्स स्थित एक संस्था से 17 लाख अमेरिकी डॉलर का लोन भी लिया। ईडी का दावा है कि एम्ब्रेयर लेगेसी 600 विमान और आगस्ता हेलिकॉप्टर खरीदने के बाद इन्हें टीएमसी को ही किराये पर दे दिया गया, जबकि इनकी खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया धन कथित तौर पर टीएमसी की ही राशि से आया था। इसके बाद विमान और हेलिकॉप्टर के उपयोग के नाम पर बड़ी रकम का भुगतान भी किया गया। ईडी का कहना है कि इस पूरे लेनदेन का वास्तविक लाभार्थी कौन है और इन वित्तीय व्यवस्थाओं का वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसकी जांच अभी जारी है.

टीएमसी फंड से लगजरी जेट खरीद, उसे खुद किराये पर ले रही थीं ममता!

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पार्टी के तीन बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए गए हैं। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं, जिनसे यह संदेह पैदा हुआ है कि पार्टी के पैसों से एक लगजरी बिजनेस जेट और एक वीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदा गया, लेकिन बाद में उन्हीं विमानों को किराए पर लेकर इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार है जब ईडी किसी राजनीतिक दल की फंडिंग की स्वतंत्र रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के अकाउंट की जांच दिल्ली आबाकारी नीति मामले के तहत की गई थी। यह पूरा मामला कोलकाता स्थित एविएशन मैनेजमेंट और लीजिंग कंपनी Carewell Aviation India Pvt Ltd पर ईडी की छापेमारी के बाद सामने आया। एजेंसी के मुताबिक, यह कंपनी सितंबर 2021 में बनाई गई थी। इसी साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। ईडी के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच TMC के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन को ट्रांसफर किए गए, जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने इनमें से 82.96 करोड़ रुपये एक अन्य नई कंपनी को भेज दिए। ईडी का आरोप है कि झ्रूष्ट से मिले पैसों का इस्तेमाल कर केयरवेल एविएशन ने करीब 112 करोड़ रुपये की लागत से एक Embraer Legac4 600 बिजनेस जेट और एक Agusta 109 एसपी हेलिकॉप्टर खरीदा.

सेंसेक्स 238 अंक उछला निफ्टी 23,963 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार ने गुरुवार के कारोबारी सत्र में मजबूत वापसी की। दिनभर सीमित दायरे में कारोबार करने के बावजूद आखिरी घंटों में खरीदारी बढ़ने से प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पीएसयू बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जबकि आईटी सेक्टर दबाव में रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 238.22 अंक यानी 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ 76,741.82 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई का निफ्टी50 80.75 अंक यानी 0.34 फीसदी चढ़कर 23,962.80 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी50 में सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में शामिल रहे। इन शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली। मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ व्यापक बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिली।

महंगा होगा कुकिंग ऑयल कमजोर मानसून से बढ़ी चिंता

नईदिल्ली। आयातित खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों और कमजोर मानसून के कारण घरेलू तिलहन उत्पादन पर संडराते खतरे के चलते आने वाले महीनों में रसोई का बजट और बढ़ सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में महंगी खरीद, बढ़ती परिवहन लागत और घरेलू उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में जल्द राहत मिलने की संभावना कम है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के अनुसार, बुधवार को सरसों तेल का औसत खुदरा मूल्य 193.54 रुपए प्रति किलोग्राम, सोयाबीन तेल 163.10 रुपए प्रति किलोग्राम और पाम तेल 147.37 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.74 प्रतिशत, 11.53 प्रतिशत और 12.87 प्रतिशत अधिक है।

61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनाया नया यूपीआई फीचर

नईदिल्ली। जून में फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिये करीब 61.1 करोड़ यूपीआई ट्रांज़ेक्शन किए गए, जिनकी कुल वैल्यू 25,416 करोड़ रुपए थी। यह महीनेभर में हुए कुल यूपीआई का 2.7 फीसदी है। बायोमेट्रिक फीचर पिछले साल शुरू किया गया था। नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला ने कहा कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बढ़ते इस्तेमाल से साफ है कि यूजर्स तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट अनुभव को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बैंक और यूपीआई ऐप पहले से ही अपने ग्राहकों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे ज्यादा यूजर्स पेमेंट के इस सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके को अपनानेगे, इसका इस्तेमाल और बढ़ेगा।

तेल कीमतों में नरमी से विदेशी निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

नईदिल्ली। करीब डेढ़ साल तक भारतीय बाजारों से दूरी बनाए रखने के बाद वैश्विक निवेशकों का रुझान एक बार फिर भारत की ओर बढ़ने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, रुपए में स्थिरता और सरकार की नीतिगत पहल से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंक अब भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार को आकर्षक निवेश विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। सिटीग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज और मैक्करी जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत संकेतकों ने निवेशकों की धारणा बदलनी शुरू कर दी है। सिटीग्रुप की भारत टीवी ने अमेरिकी के 36 संस्थागत निवेशकों से मुलाकात के बाद कहा कि भारतीय परिस्परितियों में निवेश की रुचि तेजी से लौट रही है।

केरल-तमिलनाडु के श्वेत पत्र ने राजकोषीय सुधार की जरूरत दिखाई

आर कविता राव

इस साल संपन्न विधान सभा चुनावों के बाद तीन राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सत्ता बदली है। इनमें दो राज्यों में नई सरकारों ने अपने समक्ष मौजूद चुनौतियां स्पष्ट करने के लिए ‘राज्य की आर्थिक स्थिति’ पर श्वेत पत्र जारी किए हैं। माना जा रहा है कि चुनौतियों की शिनाख्त करना करना उन्हें बेअसर करने के उपाय करने की दिशा में पहला कदम है।

कर्ज का स्तर बढ़ने की चिंता के अलावा ये दोनों दस्तावेज (दोनों राज्यों के) आय और खर्च से जुड़ी कुछ समान चिंताओं की ओर भी ध्यान खींचते हैं। खर्च के मामले में वे राजस्व खर्च में तय देनदारियों के बड़े हिस्से और पूंजीगत व्यय के लिए बची सीमित गुंजाइश की ओर इशारा करते हैं। पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में दीर्घ अवधि की वृद्धि का आधार होता है।

केरल ने जिक्र किया है कि उसका तय खर्च (जिसमें वेतन-भत्ते, पेंशन और ब्याज का भुगतान शामिल है) राजस्व आय का 77 प्रतिशत है जबकि तमिलनाडु ने यह आंकड़ा राजस्व आय का 64 प्रतिशत बताया है। इसके उलट, पूंजीगत व्यय केरला के लिए 1.3 प्रतिशत और तमिलनाडु के लिए 1.44 प्रतिशत तक ही सीमित है। दोनों राज्य व्यय के मामले में दो और चिंताओं की ओर इशारा करते हैं यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की देनदारियां और बकाया राशि के रूप में राज्य की मौजूदा देनदारियां पूरी करने में आने वाली चुनौतियां की बात करते हैं।

आय के मामले में श्वेत पत्र इन राज्यों के अपने कर राजस्व की वृद्धि में आई सुस्ती उजागर करते हैं। केरल का श्वेत पत्र अपने



कर राजस्व में आई गिरावट की तुलना अपने ही पिछले प्रदर्शन और दूसरे समान राज्यों से करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले उसके कर राजस्व का अनुपात वर्ष 2015-16 में 6.94 प्रतिशत से घट कर हाल के वर्षों में 6.41 प्रतिशत हो गया है जो कम वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) का प्रदर्शन है। तमिलनाडु का श्वेत पत्र भी इस अनुपात में गिरावट की ओर इशारा करता है। वर्ष 2006-07 में यह 8.94 प्रतिशत से उच्च स्तर पर था जो वित्त वर्ष 2025-26 में घट कर 5.45 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया है।

इन श्वेत पत्रों का अध्ययन करने से कुछ सवाल उठते हैं। पहला, क्या पहचानी गई वित्तीय चुनौतियां केवल इन दो राज्यों तक ही

सीमित हैं या यह समस्या और भी व्यापक है? दूसरा, क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस विकल्प मौजूद हैं?

राज्यों के पास राजस्व प्रारितियों में बढ़ोतरी के जरिये उपलब्ध वित्तीय गुंजाइश समझने के लिए हम वर्ष 2024-25 तक के जांचे (ऑडिट किए हुए) आंकड़ों और मार्च 2026 (2025-26) के कुल मासिक खातों से अवलोकन करते हैं। कोविड-19 महामारी से पूर्व सभी राज्यों की राजस्व प्रारितियों में सालाना औसत बढ़ोतरी दर 10 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2019-21 के दौरान यह दर गिरकर लगभग शून्य प्रतिशत हो गई। अगले दो वर्षों में बढ़ोतरी की दर तेजी आई (वर्ष 2021-22 में 25 प्रतिशत और 2022-23 में 13 प्रतिशत)। इसके बाद स्पष्ट र सुस्ती देखी गई यानी वर्ष 2023-24 में यह दर 8 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2024-25 में यह 6.8 प्रतिशत थी। मासिक खातों के आंकड़ों को देखें तो

यह मामूली सुधार कर 7.3 प्रतिशत हो गया है। बड़े राज्यों को मिलाकर भी ऐसा ही रुझान दिखता है। उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल की बात की जाए तो राज्यों की आर्थिक स्थिति पर दबाव इस बात से साफ पता चलता है कि राज्य राजस्व घाटा पूरा करने के लिए अपने राजकोषीय घाटे का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मोर्चे पर भी महामारी के बाद स्थिति में साफ सुधार दिखाई दे रहा है और वर्ष 2022-23 में राजस्व अधिशेष वाले बड़े राज्यों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। मगर इसके बाद स्थिति बदल जाती है। राजस्व अधिशेष दर करने वाले राज्यों की संख्या कम रही। दूसरी तरफ, राजस्व घाटा पूरा करने के लिए राजकोषीय घाटे का 50 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल करने वाले बड़े राज्यों की संख्या वर्ष 2023-24 में चार से बढ़कर वर्ष 2024-25 में छह और 2025-26 में आठ हो गई है।

सुशासन, विकास और जनकल्याण ही सरकार की पहचान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समोदा में लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत समोदा में आयोजित कार्यक्रम में 128 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी कीं।

मुख्यमंत्री साय ने ग्राम पंचायत रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉप डैम निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में अहाता निर्माण, नगर पंचायत समोदा के पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण तथा ग्राम तुलसी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी विद्यालय में उन्नयन की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन, विकास और जनकल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि क़मोदी



की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार की कार्यशैली और जनविश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 10 लाख से अधिक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों से

3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है तथा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 28 किशतों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी सोच के साथ बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों

में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। पात्र उपभोक्ता मोर बिजली मोबाइल एप अथवा वेबसाइट के माध्यम से सितंबर तक पंजीयन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कार्यक्रम में कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत देव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आरंग विधानसभा क्षेत्र को अब तक 858 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास और सुशासन की नई दिशा स्थापित हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत आंवला पौधारोपण किया। उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की तथा जिला प्रशासन के मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया।



■ दीदी के गोठ में गूंजी आत्मनिर्भर बस्तर की आवाज
■ लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों ने बढ़ाया महिलाओं का आत्मविश्वास

इनसे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

स्वरोजगार से बदल रही महिलाओं की जिंदगी

चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने कहा कि बस्तर की महिलाएं अब केवल परिवार की ज़िम्मेदारी तक सीमित नहीं हैं। वे मुर्गीपालन, बकरीपालन, मत्स्यपालन, सब्जी उत्पादन और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने भी महिलाओं की मेहनत और लगन की सराहना करते लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों ने महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वरोजगार के प्रति नया उत्साह जगाया।

लखपति दीदियों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम में चपका की श्रीमती नीतू झा, सुलेंगा की श्रीमती सुगनी कश्यप और इरपा की श्रीमती हेमबती नाग सहित कई सफल लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाण-पत्र और सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कोडगांव जिले की श्रीमती नम्रता पटेल ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि बिहान योजना के तहत बैंक लिंकेज और 5 लाख रुपये के ऋण की सहायता से उन्होंने अपने %अमृत तुल्य% चाय एवं नाश्ता कैफे का विस्तार किया। आज उनके कैफे से प्रतिदिन लगभग 5 हजार रुपये की आय हो रही है।

कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने सरकारी योजनाओं से मिले लाभ और अपने अनुभव साझा किए। संवाद, सम्मान और प्रेरणा से भरपूर यह आयोजन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बस्तर के संकल्प को नई मजबूती देने वाला साबित हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर श्री आकाश छिक्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

नकटी में विधायक आवास नहीं तो मकान क्यों तोड़ा गया: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नकटी में गरीबों का मकान तोड़ने के बाद सरकार कहती है, वहां विधायक आवास नहीं बनाया जायेगा। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव, मंत्री केदार कश्यप पत्रकारवार्ता लेकर कहते हैं कि वहां पर विधायको के लिये मकान बनाने का कोई योजना नहीं है। आज ओ.पी. चौधरी का भी बयान आया है वहां विधायक आवास नहीं बनाया जायेगा। अक्टूबर 2024 में आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद कलेक्टर को पत्र लिखकर षष्ठम विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु नकटी में अतिक्रमण भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये कहा था। इस पत्र में आयुक्त छ.ग. गृह निर्माण मंडल के पत्र क्र. 58 दिनांक 25.09.2024 का हवाला भी दिया है। यह पत्र बताता है कि भाजपा नेताओं की हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी सरकार की गलती छुपाने झूठ बोला है।



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जब भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे, उस समय उनको बताते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्पष्ट किया कि नकटी गांव में विधायकों के लिये आवास हेतु जगह चिह्नित है।

गरीबों का आशियाना उजाड़ने के बाद सरकार सफाई दे रही है। सरकार को अपनी गलती का अहसास हो गया है तो वहीं पर तोड़े गये मकान फिर बनाये जाये तथा प्रभावितों को मुआवजा दिया जाये।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार के किस मंत्री को फायदा पहुंचाने तथा किस भाजपा नेता के रिश्तेदार रजनीश चंद्राकर और नितिन अग्रवाल को फायदा पहुंचाने नकटी में तोड़-फोड़ की गयी? किसकी जमीनों के भाव गरीबों के मकान के कारण नहीं बढ़ रहे थे?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर का महादेव सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला

रायपुर। महादेव सट्टा ऐप मामले और छत्तीसगढ़ में हो रहे कथित अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

ठाकुर ने कहा कि महादेव सट्टेबाजी मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की ओमान में गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी ओर, कांग्रेस के ही कोषाध्यक्ष, जो भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा चल रहे थे, को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट है कि महादेव सट्टा कांग्रेस के संरक्षण में ही फला-फूला है। सट्टे का संचालक सौरभ चंद्राकर दुर्ग जिले से संबंध रखता है और कांग्रेस सरकार के समय लगभग आधे मंत्री इसी जिले से थे और संरक्षण व रायल्टी को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के बीच सियासी टकराव से पूरा प्रदेस वाकिफ है। इन आरोपों को छत्तीसगढ़ लाए जाने के बाद आने वाले समय में इस मामले में और भी कई बड़े नामों का खुलासा होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सट्टेरियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती आई है। इसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का लिंक भी कहीं-न-कहीं जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के लोग ही यह कहते रहे हैं कि किस प्रकार रामगोपाल



अग्रवाल एकाधिकार सिण्डिकेट बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री के सिण्डिकेट का कोषाध्यक्ष बनकर रह गए थे।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने प्रदेश में बढ़ रहे अतिक्रमण को मुद्दा भी इस दौरान प्रमुखता से उठाया और कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सही माना जाना चाहिए? एक आम आदमी का कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1200 से 1500 वर्ग फीट में फर बनाने की सोच पाता है, जबकि कुछ लोग 12 हजार-15 हजार वर्गफीट जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम सुसज्जित, विकसित और सुधर छत्तीसगढ़ चाहते हैं तो क्या इस प्रकार का अतिक्रमण करना सही है? राजनीतिक दलों, नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को इस बात का चिंतन करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस हमेशा अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देती है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मंत्री रहे अमरजीत भगत, शिव डहरिया आदि पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगा हुआ है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री पर भी कई आरोप लग चुके हैं। इस बात का चिंतन गाँवों में ज्यादा होता है। गाँव में अनेक बार देखा गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

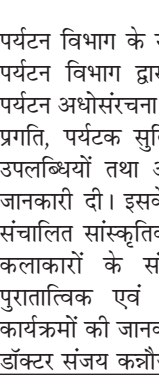
प्रमुख समाचार

सात ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विभागीय मुख्यालय 'निर्माण भवन' में प्रदेशभर में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक कार्यों की प्रगति पर बारीक नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड पर जाकर निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद रख कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अधिकारिता वी.के. भतवधरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विभाग के अभियंताओं की दक्षता और क्षमता फील्ड पर दिखनी चाहिए। प्रभावी एवं परियाममूलक कार्यों के लिए समयानुकूल नई कार्यप्रणाली और कार्य संस्कृति अपनाने पर जोर दिया। सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ तत्परता से पूर्ण कर आगामी सितम्बर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कायदेशि जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि बरसात के तत्काल बाद पूरी गति से काम शुरू हो सके। उन्होंने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूर्ण कर समय पर काम प्रारंभ कराने को कहा।

छत्तीसगढ़ बने देश का प्रमुख पर्यटन राज्य: राजेश अग्रवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से आज मंत्रालय में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास परियोजनाओं, अधोसंरचना निर्माण, प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल एवं पर्यटन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, पर्यटन अधोसंरचना विकास, प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार, विभाग की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही संस्कृति विभाग द्वारा संचालित सांस्कृतिक संरक्षण, लोककला एवं लोक कलाकारों के संवर्धन, सांस्कृतिक आयोजनों, पुरातात्विक एवं धरोहर संरक्षण तथा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी संस्कृति विभाग के संचालक डॉक्टर संजय कन्नौज द्वारा दी गई।



नगर निगम की विशेष सामान्य सभा सम्पन्न

रायपुर । रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास कार्यों, मानसून के दौरान जलभराव, सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभा में जनप्रतिनिधियों ने शहर के विभिन्न वार्डों में जलभराव की समस्या, नालों की नियमित सफाई तथा वर्षा जल निकासी की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। निगम प्रशासन को निर्देश दिए गए कि बारिश के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। विशेष सामान्य सभा के दौरान बारिश के कारण निगम मुख्यालय की छत से पानी टपकने की घटना भी सामने आई, जिस पर भवन की आवश्यक मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए गए।

एचपीवी टीकाकरण से मिलेगा सर्वाइकल कैंसर से बचाव

रायपुर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल कैंसर) और अन्य जननांग कैंसर से बचाता है। यह टीका 9 से 15 वर्ष की आयु के लोगों के लिए अनुशंसित है। इसे यौन गतिविधि शुरू होने से पहले लगवाना सबसे प्रभावी माना जाता है। खुराक की संख्या और समय-सीमा व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है। 9 से 14 वर्ष के बच्चों को 6-12 महीने के अंतराल पर 2 खुराक दी जाती हैं। 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 6 महीने की अवधि में 3 खुराक की आवश्यकता होती है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 से 18 जुलाई 2026 तक सुकुमा जिले में विशेष एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को जन्मदी की स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण बन सकता है। समय पर लगाया गया एचपीवी टीका इस संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम करता है और भविष्य में गंभीर बीमारी से बचाव प्रदान करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि 9 से 15 वर्ष की आयु में लगाया गया एचपीवी टीका अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। यह टीका के केवल सर्वाइकल कैंसर से बचाव करता है।

एक वर्ष में 12 एपिसोड के माध्यम से हजारों महिलाओं तक पहुँची सफलता की कहानियां ‘दीदी के गोठ’ माताओं-बहनों के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम

रायपुर। 'दीदी के गोठ' कार्यक्रम प्रदेश की माताओं-बहनों के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आजीविका, नवाचार और स्वरोजगार से जुड़ी अत्यंत रोचक एवं प्रेरक जानकारियां मिल रही हैं। एक सफल दीदी की कहानी हजारों अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है और यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 'दीदी के गोठ' वार्षिकोत्सव-2026 एवं संकुल स्तरीय संगठन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर 'दीदी के गोठ' काँफी टेबल बुक, 'बिहान वाणी' त्रैमासिक पत्रिका तथा 'मोर गांव मोर पानी' पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाली दीदियों को सम्मानित किया तथा 'दीदी के गोठ' के 12 एपिसोड पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर महिलाओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित 'दीदी के गोठ' फोटो गैलरी का अवलोकन किया तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद कर उनके नवाचारों एवं आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली और उन्हें निरंतर आगे



बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दुर्ग जिले से वरुंअल माध्यम से जुड़ी लखपति दीदी विद्या निपाद से पूरा कर लिया है और अब तक 12 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को एक सफल दीदी अपनी संघर्ष एवं सफलता की कहानी स्वयं अपनी बोली में साझा करती हैं, जिससे प्रदेशभर की महिलाओं को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है।

मुख्यमंत्री ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। 'दीदी के गोठ' ने एक वर्ष का सफल सफर पूरा कर लिया है और अब तक 12 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को एक सफल दीदी अपनी संघर्ष एवं सफलता की कहानी स्वयं अपनी बोली में साझा करती हैं, जिससे प्रदेशभर की महिलाओं को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। वेदों में कहा गया है - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज महिलाएँ बिहान से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। कोई झेन दीदी बनी है, कोई राजमिस्री, कोई ऑर्गेनिक खेती कर रही है, तो कोई सेटरिंग प्लेट , पशुपालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की लखपति दीदियां आने वाले समय में करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और विकसित भारत तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

नवा रायपुर में 350 एकड़ का बॉटनिकल गार्डन विकसित होगा स्मार्ट सिटी को मिलेगी नई पहचान

रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर को हरित और पर्यावरण-अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में विशाल बॉटनिकल गार्डन विकसित करने की योजना पर कार्य आगे बढ़ रहा है।

प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डन में देश-विदेश की विभिन्न प्रजातियों के पौधे, औषधीय वनस्पतियाँ, थीम आधारित उद्यान, जल ट्रेंक तथा पर्यटकों और नागरिकों के लिए आधुनिक सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को

बढ़ावा देना, जैव विविधता का संवर्धन करना तथा नवा रायपुर को एक प्रमुख पर्यटन एवं प्रकृति केंद्र के रूप में स्थापित करना है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नवा रायपुर में सड़क, हरित क्षेत्र, डिजिटल अधोसंरचना, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी विकास से जुड़े अन्य कार्य भी निरंतर किए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि बॉटनिकल गार्डन के विकसित होने से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना नवा रायपुर को देश के प्रमुख हरित और आधुनिक शहरों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

